www.ghoonghatkibagawat
www.ghoonghatkibagawat
ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 47 | गोरखपुर, 08 जून 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

▶ विदेश मंत्री जयशंकर ने सभी अफवाहों का दिया स्पष्ट जवाब

'पाकिस्तान के अनुरोध के बाद ही रोका गया ऑपरेशन सिंदूर'



▶ बयान को गलत तरीके से पेश करके राजनीति

▶ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते

▶ पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमलों ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी चोट पहुंचाई

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनीं हुई थी ऐसे में तीन से चार दिन तक चले ताबड़तोड़ हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया गया। सीजफायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया। इसके बाद पूरे विश्व में शुरूआत में ये संदेश फैल गया कि भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर ट्रंप मे कराया था। इसके बाद भारत सरकार ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर दोनों देशों द्वारा लिया गया स्वंम का निर्णय था। अब एक बार फिर से भारत सरकार ने साफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के बीच डीजीएमओ वार्ता के बाद ही भारत ने रोका था ऑपरेशन सिंदूर।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि डीजीएमओ ने पाकिस्तान को उसके क्षेत्र में आतंकी शिविरों पर भारत की ओर से हमला किए जाने के बारे में जानकारी हमलों को अंजाम दिए जाने के बाद बाद दी थी।

सूत्रों ने यह जानकारी दी। जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से कभी बात नहीं की और कथित अमेरिकी हस्तक्षेप के बारे में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान को रोकने का निर्णय पाकिस्तान के अनुरोध के बाद द्विपक्षीय रूप से लिया गया था। मंत्री ने विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' को तभी रोका गया जब पाकिस्तान के डी-जीएमओ ने इसे रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अमेरिकी मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी, जयशंकर पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आतंकी शिविरों पर भारतीय हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था।

कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना का जिक्र करते हुए जयशंकर ने सांसदों से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ नेता उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके राजनीति कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने इस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तानी पक्ष से बात की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने बैठक में सांसदों को बताया कि केवल दोनों देशों के डीजीएमओ ने एक-दूसरे से बात की और किसी अन्य भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तानी पक्ष से बात नहीं की। मंत्री ने सांसदों को यह भी बताया कि पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाई रूकवाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी, वहीं अमेरिकी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि पाकिस्तान को भारत से सीधे बात करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत से पाकिस्तान से बात करने का आग्रह कर रहा था और उसे बताया दिया गया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान सांसदों द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' को रोकने और अमेरिकी 'हस्तक्षेप' के बारे में पूछे गए कई सवालों के जवाब में बताया कि डीजीएमओ ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सूचित किया था कि अगर वे गोलीबारी करेंगे, तो भारत जवाबी गोलीबारी करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमलों ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी चोट पहुंचाई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने दुनिया भर में पाकिस्तान को ह्यबेनकाबह्ण करने में सभी सांसदों से सहयोग मांगा। मंत्री ने सांसदों से पाकिस्तान के दुष्प्रचार में न आने और पड़ोसी देश द्वारा फैलाई गई अफवाहों पर विश्वास न करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जहां कई देशों ने आतंकी शिविरों पर हमला करने में भारत की भूमिका का समर्थन किया है, वहीं चीन, अजरबैजान और तुर्किए जैसे बहुत कम देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट संदेश को दुनिया के सामने रखने के लिए सांसदों के बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजा है।

सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की अपील

राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच करेगी सीबीआई

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वे मेघालय में इंदौर के एक जोड़े के लापता होने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाएं। राजा रघुवंशी के मृत पाए जाने और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के लापता होने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम यादव ने शोकाकुल परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा, मध्य प्रदेश इस संकट की घड़ी में सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात की है।

यादव ने आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मेघालय में अपने समकक्षों के साथ लगातार समन्वय में हैं ताकि घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा, मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यह मामला 23 मई को हनीमून के दौरान शिलांग में लापता हुए जोड़े से जुड़ा है। राजा का शव बाद में सोहरा के पास एक घाटी में मिला, जबकि सोनम का पता नहीं चल पाया है। हनीमून पर मेघालय में लापता हुई इंदौर की 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी के परिवार ने पहले केंद्र सरकार से मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आग्रह किया था। यह अपील मेघालय पुलिस द्वारा की गई लापरवाही और अप्रभावी जांच को लेकर बढ़ती निराशा के बीच की गई है।

अमित शाह ने की नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाने वाले अधिकारियों से मुलाकात

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी, जिसके कारण शीर्ष नक्सल नेताओं को मार गिराया गया। शाह ने यह भी कहा कि वह सफल अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जवानों से मिलने जल्द ही छत्तीसगढ़ आएंगे। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा किहाल ही में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारियों से मुलाकात की और इन अभियानों की ऐतिहासिक सफलता पर उन्हें बधाई दी। मैं उन जवानों से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं जिन्होंने अपनी बहादुरी से इन अभियानों को सफल बनाया और जल्द ही छत्तीसगढ़ जाकर उनसे मिलूंगा।

उन्होंने भारत को नक्सलवाद के अभिशाप से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के संकल्प को दोहराया। 6 जून को, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नक्सलवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से सफल



अभियानों, आगे के रास्ते और राज्य के विकास पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे। अपने दौरे के दौरान, सीएम साय ने गृह मंत्री शाह और अभियानों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से भी मुलाकात की। एक महीने से भी कम समय में, दो नक्सल विरोधी अभियानों ने प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के दो शीर्ष कमांडरों को मार गिराया है। 5 जून को, अधिकारियों ने पुष्टि की कि एक शीर्ष नक्सल नेता सुधाकर (उर्फ गौतम) का शव मिला है। 21 मई को, तीन सप्ताह से भी कम समय पहले, बसव राजू का शव बरामद किया गया था। राजू केंद्रीय समिति पोलित ब्यूरो के सदस्य और सीपीआई (माओवादी) के महासचिव थे, जिन्हें व्यापक रूप से नक्सल आंदोलन की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, गौतम एक वरिष्ठ माओवादी नेता था जो कई हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार था, जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष आदिवासी नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई। उसकी मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है और माओवादी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर दंडकारण्य क्षेत्र में। उसके मारे जाने से प्रतिबंधित और गैरकानूनी माओवादी संगठन की पहले से ही कमजोर होती ताकत को काफी झटका लगने की उम्मीद है। इससे पहले, सीएम साय ने ऐसे ऑपरेशनों को अंजाम देने वाले जवानों की बहादुरी के लिए उन्हें सलाम किया।

विधानसभा में पेश होगा सशस्त्र बलों की तारीफ वाला प्रस्ताव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी सोमवार से शुरू होने वाले आगामी मानसून सत्र में एक प्रस्ताव पेश करने वाले हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की जाएगी और हमले के बाद बैसरन घाटी में सेना की प्रतिक्रिया की सराहना की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि प्रस्ताव में ह्यऑपरेशन सिंदूरह्ण का जिक्र नहीं किया जाएगा। मंगलवार को सदन में प्रस्ताव पेश किए जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री का सोमवार को नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन राज्य प्रशासन के सूत्रों के अनुसार उनकी योजना स्थगित कर दी गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने स्पष्ट बयान दिया है और हमारी पार्टी का रुख भी बिल्कुल साफ है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति में टीएमसी इस पर कोई राजनीति नहीं करेगी। यह देश का मामला है। हम जवानों के साथ हैं, देश के साथ हैं, हम सब मिलकर श्रद्धांजलि देंगे। यह समय है जब सभी को एकजुट होना चाहिए और केंद्र सरकार जो भी रुख अपना रही है, उस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह टीएमसी है। इसलिए, हमारे विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, वह हमारे जवानों के समर्थन में होगा और देश विरोधी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ होगा। हम इस पर कोई दलगत राजनीति नहीं करना चाहते।

प्रस्ताव में कहा गया है, यह सदन 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर की बैसरन घाटी में निर्दोष पर्यटकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा आघात और पीड़ा व्यक्त करता है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल के तीन सहित 26 निर्दोष लोगों की दुखद जान चली गई। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आगामी मानसून सत्र में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में पेयजल मुद्दों और गंगा नदी के कटाव पर प्रस्ताव पेश करेगी। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण संशोधन विधेयक भी ला सकती है, जिसमें ओबीसी सूची में 76 नई जातियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सोमवार को पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी सूची में 76 नई जातियों को जोड़ने को मंजूरी दी, जिससे कुल जातीय समूहों की संख्या 140 हो गई।

किसान कल्याण के लिए प्रयास और अधिक उत्साह के साथ जारी रहेंगे: पीएम



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान उनकी सरकार की अनेक पहलों से किसानों की समृद्धि बढ़ी है और कृषि में बदलाव सुनिश्चित हुआ है। मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमारे किसान भाई-बहनों को पहले जहां छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी उधार लेने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं बीते 11 साल में हमारी सरकार के निर्णयों से उनका जीवन बहुत आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर किसान फसल बीमा, हमने उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। अब एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी से देश के अन्नदाताओं को ना सिर्फ फसलों की उचित कीमत मिल रही है, बल्कि उनकी आय भी बढ़ रही है। मोदी ने कहा कि हमारे मेहनती किसानों की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। पिछले 11 वर्षों में, हमारी विभिन्न पहलों ने किसानों की समृद्धि को बढ़ावा दिया है और कृषि क्षेत्र में समग्र परिवर्तन सुनिश्चित किया है। हमने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो बहुत फायदेमंद रहे हैं। आने वाले समय में किसान कल्याण के लिए हमारे प्रयास और अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। नरेन्द्र मोदी 20 जून को ओडिशा पहुंचेंगे और राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे। यहां एक वरिष्ठ मंत्री ने शनिवार को यह जानकारी दी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि 12 जून को राज्य में भाजपा सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं लेकिन मुख्य समारोह 20 जून को होगा क्योंकि प्रधानमंत्री उस दिन राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, ओडिशा में मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार का गठन 12 जून, 2024 को हुआ था और इस वर्ष 12 जून को सरकार का एक साल पूरा हो रहा है। हालांकि, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुख्य समारोह 20 जून को होगा।

प्लाईवुड फैक्टरी में लगी आग, मची अफरातफरी, कारण अज्ञात



लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बीकेटी में गत शनिवार को दोपहर प्लाईवुड फैक्टरी में आग लग गई। आग से मौके पर अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने तीन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। एफएसओ बीकेटी प्रशांत कुमार के मुताबिक, शनिवार को दोपहर 2:39 बजे इंदौरा बाग प्लाईवुड फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर तीन गाड़ियों के साथ वह और दमकल कर्मी पहुंचे। वहां देखा कि फैक्टरी में धूप में रखीं प्लाई तेजी से जल रही थीं। इसके बाद तुरंत आग के चारों तरफ घेरा बनाकर बुझाना शुरू किया गया। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग बुझा ली। एफएसओ के मुताबिक हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

साझेदार देशों को आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को समझना चाहिए: जयशंकर

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने गत दिनों नई दिल्ली में ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ व्यापक चर्चा के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख को दोहराया। भारत की 'शून्य सहनशीलता' नीति पर जोर देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत कभी भी 'बुराई करने वालों' की तुलना उनके पीड़ितों से नहीं करेगा। उनकी टिप्पणियों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा गया, विशेष रूप से नई दिल्ली की बढ़ती बेचैनी के बीच, जब ब्रिटेन सहित कई देश 7 से 10 मई के बीच सैन्य झड़प के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच समानताएं बता रहे हैं।



आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि करते हुए जयशंकर ने कहा कि देश सख्त जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करता है और अपने सहयोगियों से भी यही अपेक्षा करता है। उन्होंने हाल ही में क्षेत्रीय तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान को समान बताने वाले अंतरराष्ट्रीय आख्यानों का परोक्ष रूप से जिक्र करते हुए कहा भारत कभी भी बुराई करने वालों को उनके पीड़ितों के बराबर नहीं रखेगा। उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट निंदा के लिए ब्रिटेन के प्रति आभार व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन को स्वीकार किया।

जयशंकर ने पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की ब्रिटेन द्वारा कड़ी निंदा और भारत के साथ उसकी एकजुटता को स्वीकार किया। औपचारिक वार्ता शुरू होने से पहले टेलीविजन पर दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साझेदार इसे समझेंगे।

दो फेज में होने वाली जातिगत जनगणनाओं की तिथियां घोषित

नई दिल्ली। जातिगत जनगणना और जनगणना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार 1 मार्च, 2027 से जनगणना शुरू करेगी। ये दो चरणों में की जाएगी। वहीं, पहाड़ी राज्यों जैसे- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। जातीय जनगणना के साथ-साथ जनगणना 2 फेज में शुरू की जाएगी। इसमें देश भर में पुरुषों और महिलाओं से पूछे जाने वाले सवालों की एक लंबी लिस्ट में जाति से संबंधित एक एक जरूरी सवाल और जुड़ जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की थी कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के लिए आमतौर पर हर दस साल में जनगणना होती है और ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। 2011 की पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी।

मैरिज हाल में मचा उत्पात बिन दुल्हन लौटी बरात

बस्ती। शहर के रोडवेज के निकट एक मैरिज हॉल में डीजे पर गाना बदलने के लिए विवाद हो गया। बराती मारपीट पर आमादा हो गए। आखिरकार, बरात बिना शादी के ही लौट गई। रविवार रात संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला बाजार से बरात आई थी। बरात में शामिल कुछ लड़कों ने डीजे पर गाना बदलने के दौरान आपस में मारपीट कर लिया। इस दौरान लड़की पक्ष के लगभग चार से पांच लोग घायल हो गए। लेकिन फिर भी लड़की पक्ष के लोग शांत रहे और बरात प्रिंस मैरिज हॉल पहुंची। दूल्हा स्टेज पर बैठ चुका था और दुल्हन लाने की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच कुछ युवकों ने खाना फेंकना शुरू कर दिया।

'खाकी' को चकमा दे हो गया फरार-तलाश में जुटी पुलिस

दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट में पेशी पर आया, पुलिसकर्मियों को लगी कड़ी फटकार

देवरिया। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया पॉक्सो का आरोपी पुलिस से हाथ छुड़ाकर चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन, पकड़ नहीं पकड़ा नहीं जा सका। इस बात की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर एडिशनल एसपी उत्तरी अरविंद वर्मा और सीओ सिटी संजय रेड्डी ने पहुंचकर मामले का जायजा लिया। आरोपी को लेकर पेशी के लिए आए पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। आरोपी शिवा बांसफोड कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर का रहने वाला है। 8 अप्रैल, 2025 को महुआडीह के एक गांव की नाबालिग से दुष्कर्म का का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में गत बृहस्पतिवार को वह पेशी के लिए पुलिस कस्टडी में लाया गया था। पेशी के बाद वापस जाते समय न्यायालय परिसर से ही फरार हो गया। एएसपी नॉर्थ अरविंद वर्मा ने बताया कि एक कैदी फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने के लिये जुटी हुई है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ प्रकरण : कब्बन पार्क पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

बेंगलुरु। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हाल ही में हुई भगदड़ के मामले में गंभीर कदम उठाया गया है। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अब इस दर्दनाक हादसे को लेकर कर्नाटक पुलिस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) टीम, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए), डीएनए नेटवर्क्स और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कब्बन पार्क पुलिस ने इस मामले में स्वप्रेरणा से एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर की पुष्टि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) सेंट्रल, शेखर एच टेक्कनवर ने की है। एफआईआर में आरोपियों पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान इस घटना में शामिल सभी पक्षों की भूमिका का समुचित मूल्यांकन किया जाएगा।

एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इन धाराओं में धारा 105 शामिल है, जो गैर इरादतन हत्या के बराबर मानी जाती है। इसके अलावा, धारा 125(12) के तहत ऐसे कृत्यों का आरोप है जो अन्य लोगों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। धारा 142 अवैध जमावड़े को रोकने के लिए है, जबकि धारा 121 अपराध के लिए उकसाने संबंधी है। इसके साथ ही धारा 190 लागू की गई है, जो गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों की जिम्मेदारी निर्धारित करती है।

यह दुखद घटना आरसीबी की पहली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब जीत के बाद आयोजित एक सार्वजनिक समारोह के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हुई थी, जिसका प्रबंधन ठीक से न हो पाने के कारण भगदड़ मची। भीड़ का दबाव इतना अधिक था कि कई लोग गिर गए और आपस में टकराए, जिससे लोगों की जान





गई और कई घायल हुए।

पुलिस की जांच अभी जारी है और कई पक्षों से पूछताछ की जा रही है। आरसीबी टीम, केएससीए और आयोजकों की भूमिका को लेकर सख्त जांच की जाएगी ताकि इस तरह की त्रासदियों को भविष्य में रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन भी सुरक्षा प्रबंधों को सख्त करने के लिए कदम उठा रहा है।

बच्चा चोरी की खूनी दास्तां से गायब दिखा खौफ, फरमे में फिट होते जा रहे अभिषेक बनर्जी

अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने पाताललोक के अपने किरदार हथौड़ा त्यागी में जो कर दिखाया है, उसके पार जाने में उन्हें अभी बहुत समय लगेगा। वेदा जैसी फिल्मों में उनकी खलनायकी इसीलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि दर्शकों को अब उनके त्यागी से आगे जाने की उम्मीद है। अपूर्वा में वह इसकी कोशिश पहले भी कर चुके हैं और अब ऐसी ही एक कोशिश वह फिल्म स्टोलेन में कर रहे हैं। कुछ कुछ ह्यटेकेनह्ल के नीयाम लीसन जैसा रचने की कोशिश यहां हिंदी फिल्म ह्यस्टोलेनह्ल में की गई है। हिंदी फिल्मों के नाम अंग्रेजी में रखने का सिलसिला कोई आज का नहीं है। बरसों पुराना है और इसका बस एक ही कारण है, नई पीढ़ी के दर्शकों को अपनी ओर खींचना, जिनका दिल, दिमाग और जिगर सब हॉलीवुड फिल्मों का दीवाना हो चुका है।

दो भाइयों की मिलाई का बवाल

अनुष्का शर्मा की फिल्म 'एनएच 10' याद है आपको, कुछ कुछ वैसी ही पृष्ठभूमि में बनाई गई फिल्म है, 'स्टोलेन'। दो भाई हैं और दोनों की मिलाई होती है एक छोटे से अनजान रेलवे स्टेशन पर होती है। बड़ा वाला छोटे को लेने आया है। छोटा बात बात पर उतावला हो जाता है। स्टेशन पर से एक छोटी सी बच्ची उसकी मां के पहलू से चोरी हो जाती है। चोर की स्टेशन से निकलते समय छोटे भाई से टक्कर होती है और बच्ची की टोपी उसे वहीं जमीन पर गिरी मिलती है। बच्ची की मां समझती है, बच्चा इसी ने चुराया है। बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला है, उसके तेवर अलग हैं। दोनों भाइयों को अपनी मां की दूसरी शादी में पहुंचना है लेकिन मामला यहां चश्मदीद की गवाही में पुलिस के आते ही उलझ जाता है। छोटा वाला किसी तरह बड़े को बच्ची की तलाश करने में जुटने के लिए मना लेता है। अब फिल्म आगे क्या होनी है, यही इस फिल्म की असली कसौटी है।

कोई 90 मिनट की फिल्में इन दिनों सीधे ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों की सबसे सही अवधि मानी जाती है। 90 सेकंड की रील में खोई मोबाइल की दुनिया को 90 मिनट की फिल्म बिना बोर किए दिखा देना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, और ये चुनौती तब दोगुनी हो जाती है, जब कहानी में कहने को कुछ खास न हो। पूरा रायता बस पटकथा को



और वह भी अंधेरे में फैलाना हो। फिल्म ह्यस्टोलेनह्ल की पूरी शूटिंग और साउंड डिजाइनिंग सिनेमाघरों के लिए की गई दिखती है। फिल्म के लिखे फिल्म फेस्टिवल्स के नाम गिनने का मौका तो नहीं था लेकिन प्लेट्स देखकर लगता है कि कोई फिल्म फेस्टिवल इससे छूटा नहीं है। फिल्मफ्रीवे पर अपलोड करने के बाद जहां जहां के नोटिफिकेशन आते गए, लगता है सबमें ये फिल्म हो आई है। विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव से लेकर अनुराग कश्यप तक कोई आधा दर्जन से ज्यादा तो इसके सेलेब्रिटी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं।

अनुराग कश्यप अपनी फिल्म 'केनेडी' सिनेमाघरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके नाम का सिक्का कितना चमकदार बचा है, इसी से अंदाजा लग सकता है, लेकिन इन आधा दर्जन नामों से बिना चौंधियाए अगर ये फिल्म आप देख सकते हों, तो आपको समझ आ सकता है कि एक अच्छा विचार सोचना और उस पर एक अच्छी फिल्म बनाना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। करण तेजपाल ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। निमार्ता गौरव धींगरा और करण की ही लिखी ये कहानी है। दोनों ने मिलकर फिल्म बनाने की जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिल्म 'द ठग लाइफ' और 'हाउसफुल 5' के शोर में गुम न हो जाए तो इसे बुधवार को ही रिलीज कर दिया गया है। फिल्म पर इसे बनाने वालों और इसे रिलीज करने वालों का भरोसा ये बुधवार की रिलीज ही बयां कर देती है। फिल्म टाइमपास टाइप की फिल्म है, हां, हॉलीवुड सिनेमा पसंद करने वाले हिंदी दर्शकों को ये फिल्म कमाल लग सकती है, लेकिन, उसके लिए 90 मिनट का निवेश जरूरी है।

फिल्म 'स्टोलेन' की असल खामी इसकी पटकथा का बिल्कुल अनुमानित घटनाक्रमों के अनुसार चलते जाना है। फिल्म सुखांत होगी या दुखांत, इस पर मामला देर तक टिका रहता है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का अभिनय आधी फिल्म के बाद इसकी गवाही देने लगता है। अभिषेक की बतौर लीड हीरो ये पहली फिल्म है लेकिन युवा मनोज बाजपेयी की जगह ले पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। भीखू म्हात्रे जैसा मानसिक रूप से थका देने वाला किरदार कभी अभिषेक को मिला तो उनका कैरेट भी तभी तय हो जाएगा। शुभम ने बेचैन बालक टाइप का किरदार किया है और अपनी उद्विग्नता से प्रभावित भी किया है। फिल्म में तारीफ के काबिल काम किया है बच्ची की मां बनी मिया मैजलर ने। बीते 10-11 साल से अपना नाम बनाने की कोशिशों में लगी हैं। मामला अब जाकर जमता दिख भी रहा है। सहीदुर्रहमान का काम इस फिल्म में गौर करने लायक है। कास्टिंग डायरेक्टर्स की नजरें उन पर पहले से रही हैं, फीस उनकी इस फिल्म के बाद से बढ़नी तय है।

मोबाइल पर इसे देख पाना बड़ी चुनौती

फिल्म चूंकि बनी है फेस्टिवल वाली सोच के साथ है लिहाजा ईशान घोष की सिनेमैटोग्राफी वैसी ही सिनेमाई रियलिस्टिक टोन में रखने की कोशिश की गई है। यही फिल्म अगर चटख धूप के साथ इन्हीं लोकेशंस में शूट की गई होती तो इसका डर और ज्यादा गंभीर होता। रात में डराना तो सबसे आसान काम है, असल हॉरर वह है जो दिन में इंसान को डरा दे। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ खास सहारा, टेंशन बिल्डिंग में देता नहीं है। प्रोडक्शन डिजाइन भी औसत है। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है इसका दर्शकों की संवेदनाओं से सीधे कनेक्ट न हो पाना। घपाघर सिगरेट फूंकने वाले भी अच्छा काम करने की सोच सकते हैं, ये फिल्म का एक अच्छा टोन हो सकता था, लेकिन स्याह और श्याम के बीच की बारीक लाइन पर अटकती, भटकती ये फिल्म बस किसी तरह वन टाइम वॉच ही बनकर रह जाती है।

सोनिया गांधी की अचानक बिगड़ी तबीयत, भर्ती

शिमला (हि.प्र.)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान के अनुसार, उन्हें कुछ मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जा रही है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सोनिया गांधी ने आखिरी बार 27 मई को सार्वजनिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जब उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक शांति वन में पुष्पांजलि अर्पित की थी। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और उनके बेटे राहुल गांधी (54) को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया है। उनके साथ, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर अभियोजन शिकायत में पांच अन्य लोगों को भी नामित किया है। नेशनल हेराल्ड-एजेएल-वाईआई मामला, वाईआई के लाभकारी मालिकों और बहुसंख्यक शेयरधारकों (सोनिया गांधी और राहुल गांधी) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए कथित साजिश से संबंधित है। इससे पहले इस साल फरवरी में राज्यसभा सांसद को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। अस्पताल ने उस समय बताया था कि सोनिया गांधी को आज सुबह 8:30 बजे पेट से संबंधित समस्याओं के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हम अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं लेकिन : अनुराग कश्यप

अनुराग कश्यप की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म मेकर्स में होती है। लेकिन अनुराग की कई फिल्में आज तक रिलीज नहीं हो पाई हैं। अनुराग कश्यप अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं। वो अक्सर अपने बयानों के चलते कई बार मुश्किलों में भी घिर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही अनुराग ने मुंबई छोड़ने और इंडस्ट्री के खत्म होने की बात कही थी। अब अनुराग ने फिल्म मेकर्स की क्रिएटिविटी को लेकर निराशा और मनचाही फिल्में न बना पाने व अपनी अब तक रिलीज नहीं होने वाली फिल्मों को लेकर बात की है। एक साक्षात्कार के दौरान अनुराग ने फिल्म मेकर्स की क्रिएटिव हताशा को लेकर बात की। उन्होंने कहा, ह्लहम सभी को क्रिएटिविटी के मामले में निराश होना पड़ता है। हम अच्छी फिल्में बनाना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हें नहीं समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी अधिक अच्छी फिल्में रिलीज होंगी, उतना ही उन्हें एहसास होगा कि उन्हें एल्गोरिदम या बॉक्स ऑफिस



के आधार पर फिल्में देखने का फैसला नहीं लेना करना चाहिए। इस दौरान अपनी उन फिल्मों के बारे में भी अनुराग कश्यप ने बात की, जो बनने के बाद भी किन्हीं कारणों से रिलीज नहीं हो सकीं। निर्देशक ने कहा, मेरी पहली फिल्म 'पांच' रिलीज नहीं हुई थी। यही नहीं मेरी पांच फिल्में अभी रिलीज नहीं हुई हैं, 'पांच' उनमें से एक है। अब इन पांच में से दो फिल्में रिलीज हो रही हैं और उम्मीद है कि तीसरी फिल्म भी रिलीज होगी। अनुराग कश्यप इन दिनों अभिषेक बनर्जी की हालिया रिलीज स्टोलेन के प्रमोशन में बिजी हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई इस फिल्म से अनुराग एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। अनुराग के साथ किरण राव, निखिल आडवाणी और विक्रमादित्य मोटवानी इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म का फिल्म का निर्देशन करण तेजपाल ने किया है।

'हाउसफुल 5' में सितारों की लंबी कतार

मुंबई। अभिनेता अक्षय कुमार को जब भी मौका मिलता है वह अपनी फिल्मों के जरिये कोई न कोई अनोखा रिकॉर्ड बनाने से चूकते नहीं है। उनकी बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म 'हाउसफुल 5' शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। ह्यहाउसफुलह्ल सीरीज की इस पांचवीं फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक रिकॉर्ड ये बना लिया है कि ये अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी रिलीज साबित होने वाली है। यही नहीं देश में कॉमेडी फिल्मों के बजट के मामले में भी ये फिल्म नंबर वन हो चुकी है।

जानकारी के मुताबिक फिल्म 'हाउसफुल 5' को पूरे भारत में 5000 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया जा रहा है। किसी कॉमेडी फिल्म को इतनी बड़ी रिलीज मिलना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन, फिल्म के निमार्ता साजिद नाडियाडवाला ने अपने सारे तौर तरीके अपनाकर इसे साल की सबसे बड़ी रिलीज बनाने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी।

निर्देशक मणि रत्नम की कमल हासन अभिनीत फिल्म ह्यठग लाइफह्ल से टक्कर के बावजूद ह्यहाउसफुल 5ह्ल को रिकॉर्ड स्क्रीन काउंट मिलना अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। दिलचस्प ये है कि दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर



है, इसके बावजूद दर्शकों को एक कॉमेडी फिल्म से हमेशा ज्यादा उम्मीदें रही हैं। अक्षय की प्रस्तावित फिल्म ह्यहेराफेरी 3ह्ल के शूटिंग से पहले ही अटक जाने से भी इस फिल्म पर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। अक्षय की किसी फिल्म की इतनी बड़ी रिलीज को लेकर फिल्म जगत में काफी चचार्एं हैं।

350 करोड़ रुपये में रिलीज हो रही फिल्म

फिल्म 'हाउसफुल' का मेकिंग बजट करीब 225 करोड़ रुपये है और इसमें अक्षय को छोड़ बाकी कलाकारों की फीस का बजट करीब सौ करोड़ रुपये और जोड़ा जाए तो फिल्म 325 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचती है। फिल्म के प्रचार और प्रिंट पर करीब 25 करोड़ रुपये और खर्च होने की जानकारी ट्रेड से मिली है। 350 करोड़ रुपये खर्च कर रिलीज होने जा रही इस फिल्म को सुपरहिट होने के लिए करीब 70 करोड़ रुपये की ओपनिंग पहले दिन चाहिए होगी, जिसके आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। आमतौर पर होता यही है कि जो फिल्म अपनी लागत का 20 फीसदी रिलीज के पहले दिन निकाल लेती है, उसके हिट होने के आसार बनने लगते हैं।

'हाउसफुल 5' का निर्देशन तरुण मनसुखानी ने किया है, जो इसके पहले करण जौहर की दो फिल्में 'ड्राइव' और 'हाउसफुल 5' निर्देशित कर चुके हैं। फिल्म 'हाउसफुल 5' में सितारों की लंबी कतार है, जिनमें शामिल हैं, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, श्रेयस तलपदे, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फखरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्या शर्मा, चंकी पांडे, निकितिन धीर और जॉनी लीवर आदि। फिल्म की एडवांस बुकिंग उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही है। अंतिम सूचना तक फिल्म के करीब पांच करोड़ रुपये के डेढ़ लाख के करीब टिकट बिक सके हैं। फिल्म के दो क्लाइमेक्स होने से भी दर्शक कोई एक संस्करण देखने से बच रहे हैं।

सस्ती चाय का चक्कर:

कहीं आप तो नहीं पी रहे केमिकल की घूंट

- धंधेबाज मिलावटी चायपत्ती ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खपा रहे
- बेधड़क मिलावटी खुली चायपत्ती बेची जा रही
- एक चायपत्ती का नमूना जांच में फेल पाया गया

देवरिया। चार यार मिल जाएं तो चाय की चार घूंट चल ही जाती है, मगर सावधान रहिए। कहीं आप केमिकल वाली चाय न पी रहे हों। सस्ती, ज्यादा कड़क और गहरे रंग की चाय में बड़ा खेल है। इसमें निकोटिन के साथ केमिकल भी मिला है। यह सेहत के लिए खतरनाम है।

शहर से लेकर गांव तक बेधड़क मिलावटी खुली चायपत्ती बेची जा रही है। चायपत्ती देखने में असली दिखती है, मगर रंग गाढ़ा आए इसके लिए केमिकल मिला होता है।

सस्ते के चक्कर में लोग खुली चायपत्ती खरीद रहे हैं। दुकानदार इसे 180 से लेकर 200 रुपये किलो तक बेच रहे हैं, जिसे फुटकर चाय की दुकानों पर डिब्बे में रख दिया जाता है।

खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने काफी पहले गौरी बाजार में छापा मारकर चायपत्ती के नमूने लिए थे। इस दौरान 120 क्विंटल चायपत्ती को नष्ट भी कराया गया था। इस मामले में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीमसंबंधित दुकानदार पर अग्रिम कार्यवाही कर रही है। सूत्र बताते हैं कि धंधेबाज मिलावटी चायपत्ती ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में खपा रहे हैं। शहर में स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास की दुकानों पर यह ज्यादा बिकती है।

पिछले माह भेजा गया एक नमूना पाया गया फेलः खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग जिले में समय-समय पर चायपत्ती के नमूने लेता रहता है। एक चायपत्ती का नमूना जांच में फेल पाया गया था। जांच रिपोर्ट में अधोमाननक मिलावटी पाया गया।

ट्रंप का अमेरिका भारत के लिए विश्वसनीय रणनीति के साझेदारी नहीं

भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर दिया और प्रमुख हवाई ठिकानों पर हमला किया। तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हुए दोनों देशों ने ड्रोन और सटीक मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा किया लेकिन पाकिस्तान मे ज्यादा प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए लेकिन वे किसी भी भारतीय सैन्य प्रतिष्ठान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके। भारत के लिए निर्णायक मोड़ 10 मई की सुबह आया जब इसकी सेना ने सेना मुख्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और पाकिस्तान के परमाणु कमान निकट स्थित नूर खान सहित प्रमुख पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमले किए। इसके कुछ ही घंटों बाद सीधे अमेरिकी दबाव में युद्धविराम स्वीकार कर लिया और ट्रंप ने भारत या पाकिस्तान से पहले ही इसकी घोषणा भी कर दी । युद्धविराम उसी दिन भारतीय मानक समयानुसार 17:00 बजे प्रभावी हुआ।

ट्रंप ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने भारत को व्यापार प्रतिबंध लगाने की धरमकी दी थी। व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, 'यदि आप नहीं रु कते हैं, तो हम आपसे कोई व्यापार नहीं करने जा रहे है।' उन्होंने सऊदी अरब में फिर दोहराया, मैने युद्धविराम कराने के लिए काफी हद तक व्यापार का उपयोग किया।' यदि सच है, तो आतंकवाद का निर्यात करने वाले राज्य की रक्षा के लिए अमेरिका ने कुटनीति नहीं, बल्कि आर्थिक ब्लैकमेल का सहारा लिया। प्रश्न उठता है यदि वाशिंगटन सैन्य संकट में भारत के आचरण को निर्धारित करने के लिए व्यापार खतरों का उपयोग कर सकता है, तो अगले संकट के दौरान रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार बनाने से उसे कौन रोक सकता है ?

भारत ने अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर की खरीद में लगातार वृद्धि की है। लेकिन इस प्रकरण ने जाहिर कर दिया कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा किसी अन्य शक्ति की राजनीतिक सनक पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। भारत के सैन्य ऑपरेशन के दो दिन बाद अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मजबूत अमेरिकी प्रभाव के चलते-पाकिस्तान के लिए 2.4 बिलियन के बेलआउट को मंजूरी दे दी जो डिफॉल्ट के कगार पर खड़े देश के लिए संजीवनी की तरह है। बेलआउट का समय बता रहा था, दक्षिण एशिया में सबसे लगातार आतंकवाद प्रायोजक को पुरस्कृत किया गया। बेलआउट ने दुनिया को संकित दिया कि आप जिहादी आतंक का निर्यात कर सकते हैं और पश्चिमी संरक्षण का आनंद भी ले सकते हैं। बस, शर्त है कि आपकी स्थिति आप भू-राजनीतिक रूप से माकूल होनी चाहिए। 14 मई को उन्होंने सीरिया के स्व-घोषित राष्ट्रपति अहमद अल- शरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल-जोलानी के नाम से जाना जाता है, से मुलाकात की। मोहम्मद अल-जोलानी यूएस और यूएन द्वारा नामित आतंकवादी और सीरिया के अल कायदा सहयोगी के पुर्व नेता हैं। बीते सात मई को जम्मू-कश्मीर में 26 नागरिकों की आतंकी हमले में हत्या के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ा सैन्य आपरेशन शुरू किया।

आतंकियों ने जानी-बूझी रणनीति के तहत 22 अप्रैल को धर्म पूछ कर हिन्दू पर्यटकों को निशाना



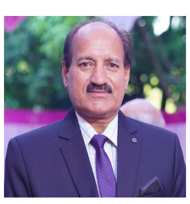
बनाया। कुछ लोगों को लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने तनाव कम करने की कोशिशें करने की बजाय आतंक के प्रायोजक का ही पक्ष लेंगे। पाकिस्तान की सेना ने दशकों से आतंकवादी गुटों को अपनी धरती से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के मंसूबे के चलते पाकिस्तान की फौज ने आतंकियों को मौन या प्रत्यक्ष समर्थन दिया। पाकिस्तान में 1947 में इस देश की स्थापना के बाद से ही फौज कर्ता-धर्ता बनी हुई हैं। इस बार भारत ने सटीकता के साथ जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान नहीं, बल्कि अमेरिका ने युद्ध की दिशा बदल दी।

ट्रंप प्रशासन ने निर्णायक क्षणों में हस्तक्षेप किया और दबाव डाल कर भारत को समय से पहले ही अपना ऑपरेशन बंद करने को कहां । ऐसा करके न केवल पाकिस्तान को उसके कृत्यों की सजा मिलने से बचाया, बल्कि अमेरिका- भारत रणनीतिक विश्वास की नींव को भी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने अपनी भूमिका के बारे में सार्वजनिक रूप से शेखी बघारी है। अपने मध्य पूर्व दौरे के दौरान रियाद से दोहा तक उन्होंने बार-बार घोषणा की कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्धविराम करवाया है। बेशक, उस विजयी स्पिन के पीछे कषैला सच भी छिपा है, अमेरिकी हस्तक्षेप शांति के बारे में नहीं था- यह एक लंबे समय से प्रमुख गैर-नाटों सहयोगी को उसके छद्म युद्ध के नतीजों से बचाने के बारे में था। भारतीय अभियान सिर्फ तीन दिनों तक चला जो आधुनिक सैन्य अभियानों में से सबसे छोटा था, फिर भी इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की।

इस बीच, ट्रंप ने कश्मीर को भू-राजनीतिक सौदेबाजी के लिए एक विकल्प के रूप में देखा हैं। आतंकवाद के निर्यात में पाकिस्तान की भूमिका पर स्पष्ट रूप से चुप रहते हुए उन्होंने कश्मीर विवाद में मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया है। कहा है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों महान राष्ट्र हैं जिन्हें इस समस्या को हल करने में मदद की जरूरत है। आतंक के लक्ष्य और इसके अपराधी के बीच इस तरह की झुठी समानता ने भारतीय सरकार और जनता, दोनों को क्रोधित किया है जो ठीक भी है। नई दिल्ली ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि- आतंक की छाया में कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारत इस पूर्व रियासत के 45 प्रतिशत हिस्से नियंत्रण रखता है, पाकिस्तान 35 प्रतिशत और चीन 20 प्रतिशत पर। फिर भी ट्रंप, युक्रेन या गाजा में संघर्षो को हल करने में विफल होने के बावजूद मानते हैं कि वे 'यह देखने के लिए काम कर सकते हैं कि क्या कश्मीर के संबंध में समाधान संभव है। हकीकत में, टूंप पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, जिसने लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को हथियार बना कर भारत के खिलाफ आतंकवादी छद्म हमलों के जरिए अपने हजारों वार को सही ठहराया है। पाकिस्तान को बचाने के बाद भी ट्रंप ने अपनी हरकतें दोहराई। 15 मई को उन्होंने भारत में आईफोन बनाने के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक को फटकार लगाई और कहा, श्मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें। इस व्यवहार का पैटर्न इस कटु सत्य को उजागर करता है कि ट्रंप का अमेरिका भारत के लिए विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार नहीं है। अमेरिका खुद को इंडो- पैसिफिक में भारत का स्वाभाविक स-झेदार बताना पसंद करता है, यह ऐसा क्षेत्र हैं जो अगली विश्व व्यवस्था का निर्धारण करेगा लेकिन कि-सी भी साझेदारी में विश्वास संकट के दौरान ही बनता है। ट्रंप ने भारत को अपने सैन्य अभियान को रोकने के लिए मजबूर किया हो सकता है -लेकिन ऐसा करके उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच विश्वास को खत्म करने में तेजी लाई है। यह दरार, जब तक कि जल्दी ठीक हो जाने के बाद, इसे ठीक करना आसान नहीं होगा।

पढ़े लिखे अनपढ़ लोग

कानून के रखवाले खुद कानून की खिल्ली हैं उड़ाते
गुनहगार को जेल में सब सुविधाएं मुहैया हैं करवाते
आम आदमी की घिस जाती है
एड़ियां न्याय पाने के लिए
गुनहगारों के लिए रात को भी
दरवाजे हैं खुल जाते
जिन पर जिम्मेवारी है भारत का भविष्य बनाने की
बच्चों के भविष्य से वही हैं खिलवाड़ कर जाते
दूसरों को नशे से दूर रहने के बारे में कैसे बताएंगे
जब वही दारू पीकर खुद विद्यालय में है आते
पढ़े लिखे समझदार
नासमझी की बात हैं कर जाते
घर का कचरा उठाकर
चुपके से रास्ते में हैं फैंक आते
अपने घर तक तो आ गई
सड़क किसी की जमीन से
मेरी जमीन से आगे नहीं जाएगी
लोगो को हैं आंख दिखाते
सड़क पर गाड़ी चलाते दादागिरी हैं दिखाते



कोई पास मांगे तो लड़ने पर हैं उतर आते
यातायात के नियमों का पालन कभी करते नहीं
दूसरों को यातायात के नियम है समझाते
नशा करना बुरी बात है सबको हैं समझाते
रोज रात को दारू पीकर हैं घर आते
चिट्टे को रोकने वाले ही चिट्टा हैं बेचते
बर्दी की मारते धौंस सरेआम हैं धमकाते
जागरूक होकर भी जो
पढ़े लिखे बन जाते अनजान
समाज को होता जिससे
नुकसान करते हैं ऐसे काम
कैसे कर सकते हैं ऐसे
जागरूक लोगों को जागरूक
अंदर से घिनौने केवल
सुनने में है इनका बड़ा नाम

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

सीवर में मौतों का अंतहीन सिलसिला

मजदूरों की जान जाना कोई नई बात नहीं। बीते छह गई को बठिंडा में एक ट्रीटमेंट प्लांट की सीवर की सफाई करने के लिए उतरे तीन लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना के एक सप्ताह बाद हरियाणा रोहतक के माजरा गांव में एक व्यक्ति और उसके दो बेटे एक दूसरे को जहरीले मेन होल से बचाने की कोशिश में एक के बाद एक मर गये। 15 गई को फर-ीदाबाद में एक मकान मालिक ने नियुक्त सफाईकर्मी को बचाने के लिए सेप्टिक टैंक में छलांग लगा दी। दोनों की ही

जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। कितना दुखद है कि आज इक्कीसवीं सदी में भी सीवर सेप्टिक टैंकों का काम मैनुअली कराया जाता है। इन टैंकों में सफाई कराने के लिए उतारने वालों को सुरक्षा उपकरण तक मुहैया नही कराये जाते हैं। दो-चार दिन के बाद गाड़ी पुरानी पटरी पर लौटने लगती है। हर घटना दर्ज होकर रह जाती है। हम कितना भी गर्व करें कि हमारा देश तकनीकी मामले में इतना आगे बढ़ गया है चांद पर सफलतापूर्वक चंद्रयान भेज रहा है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज कर रहा है पर इस बात पर शर्म महसूस होती है कि क्या हमारे पास इतनी भी क्षमता नहीं कि वह गटर या सीवर सेप्टिक टैंको की सफाई के लिए मशीनी तकनीकी विकसित कर सकें।

यदि ये क्षमता है तो फिर क्यों गटरों टैंकों की सफाई करते हुए मारे जा रहे हैं। और यदि शासन-प्रशासन की लापरवाही से मौतें हो रही हैं तो फिर इन्हें मौतें नहीं बल्कि हत्याएं कहा जाएगा। साल- 1993 में पहली बार सीवरों की मैनुअल सफाई और मैला ढ़ोने को प्रथा पर बैन लगाया गया था। इसके 20 साल बाद मैनुअल स्केवेजिंग एक्ट-2013 के माध्यम से इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। कानून के अनुसार- अगर मजदूरों को परिस्थितिवश अगर सीवर में उतरना पड़ता है- को उनको 27 दिशानिदेर्शों का पालन करना पड़ता है। होगा। इसके बाद भी आए दिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मजदूरों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी सीवर में सफाई के दौरान जाने जानेवाले मामलों अलग-अलग से सामने आते रहे है। सामाजिकता न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्य सभा में आंकडे बताए थे कि पिछले 31 सालों में 12648 जानें जा चुकी है। सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान सबसे ज्यादा 253 जाने तमिल नाडु में गई। उसके बाद गुजरात में 183, उत्तर प्रदेश में 133 और दिल्ली मे 116 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के पास चांद तक पहुंचने, की तकनीक है लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए आज भी मशीनों की कमी है। यही वजह है कि मजदूर उस जहरीली गैस वाले टैंकरों में उतर कर खुद सफाई करते हैं। कई बार तो उनकी जान तक चली जाती है।

विडंबना है कि रोजगार के रूप में हाथ से सफाई के रोजगार पर प्रतिबंध सफाई कर्मियों के पुनर्वास अधिनियम-2013 तथा खतरनाक सफाई प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के वावजूद मौतों का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे मामलों में सुरक्षा प्र-ोटोकाल की अनदेखी की जाती है। कानून के मुताबिक सफाई एजेंसियों के लिए सफाई कर्मचारियों को मास्क, दस्ताने जैसे-सुरक्षा उपकरण देना अनिवार्य है।

साहित्य आज साधना नहीं, सौदेबाजी का बाजार बनता जा रहा है। नकली संस्थाएं ₹1000-₹2500 लेकर 'राष्ट्रीय' और 'अंतरराष्ट्रीय' पुरस्कार बांट रही हैं। यह केवल साहित्य नहीं, भाषा की भी हत्या है। सहयोग राशि के नाम पर सम्मान बिक रहा है, और सच्चे साहित्यकारों की साधना उपेक्षित हो रही है। अब समय आ गया है–इन आयोजनों का बहिष्कार करें, पदार्फाश करें, और साहित्य को बाजारू अपवित्रता से बचाएं। पुरस्कार रचना की गरिमा हों, न कि डिजिटल भुगतान का पुरस्कार! यदि कोई पुरस्कार 'सहयोग राशि' से खरीदा जा सकता है, तो वह पुरस्कार नहीं, एक बाजारू तमाशा है। साहित्य आत्मा की भाषा है, न कि ट्रॉफियों की भीड़। नकली आयोजनों की नकल से हिंदी ही नहीं, साहित्य की आत्मा घायल हो रही है। अब समय आ गया है कि हम साहित्य को ह्लसेल्फी इवेंटह्व से निकालकर सच्ची साधना के मंच पर वापस लाएं।

पुरस्कारों का सौदा: साहित्य के बाजार में बिकती संवेदनाएं

साहित्य, आत्मा की पुकार है। वह सर्जक की साधना का फल होता है – तप, त्याग और संवेदना की अभिव्यक्ति। लेकिन आज, जब हम चारों ओर नजर डालते हैं, तो पाते हैं कि यह साधना अब ₹सहयोग राशि₹ और ₹नामांकन शुल्क₹ की दुकान पर बिक रही है। पुरस्कार अब साधना की स्वीकृति नहीं, पैसे की नीलामी हो गए हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है – क्या सचमुच साहित्य का मूल्य अब बैंक ट्रांजैक्शन से तय होगा?

साहित्य के नाम पर चलती मंडी

आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मेल पर साहित्यिक आयोजनों के नाम पर संदेश आते हैं झ ह्लसिर्फ ₹1000 में नामित हों, ₹2500 में पुरस्कार पाएं।ह्व कुछ तथाकथित संस्थाएं और व्यक्ति ह्यराष्ट्रीयह्, ह्यअंतरराष्ट्रीयह्, ह्यगौरवह्, ह्यरत्नह् जैसे भारी-भरकम शब्दों से सजे पुरस्कारों का जाल बिछाकर साहित्यप्रेमियों को लुभाते हैं। सच्चाई यह है कि पुरस्कार नहीं, सम्मान की नीलामी हो रही है। इन आयोजनों के अधिकांश आयोजक एक जैसी वेबसाइटें, नकली अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के नाम और सोशल मीडिया प्रचार का सहारा लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं। वे एक निश्चित शुल्क लेकर एक ट्रॉफी, सटि-फिकेट और कभी-कभी एक ऑनलाइन समारोह की व्यवस्था करते हैं, जो केवल आत्मप्रशंसा का साधन होता है, न कि वास्तविक मान्यता।

सहयोग राशि या पुरस्कार की दलाली?

इन आयोजनों के पीछे अक्सर एक चतुर चाल होती है – इसे ह्लसहयोग राशिह्व या ह्लप्रेस रिलीज खर्चह्व कहकर नैतिक जामा पहनाया जाता है। पुरस्कार एक साधक को उसके योगदान पर दिया जाना चाहिए, न कि उसकी जेब देखकर। जब कोई लेखक अपनी मेहनत से एक रचना गढ़ता है, वह अपने समय, जीवन और संवेदना का अंश उसमें उड़ेलता है। और फिर कुछ लोग आते हैं – पैसा दो, पुरस्कार लो – क्या यह साहित्य की आत्मा का अपमान नहीं? यहां साहित्य एक उत्पाद बन गया है और लेखक उपभोक्ता। पुरस्कार की शर्तें तय नहीं होतीं उनके रचनात्मक मापदंड पर, बल्कि वढकभुगतान और स्क्रीनशॉट की पुष्टि पर होती हैं।

भाषा की दुर्गति के सौदागर

ऐसे आयोजनों के जरिए न सिर्फ साहित्य को ठगा जा रहा है, बल्कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के नाम पर योजनाबद्ध गिरावट फैलाई जा रही है। जो सम्मान कभी राष्ट्रगौरव का प्रतीक होता था, वह अब टिकट खरीदकर पाई जाने वाली वस्तु बन गया है। यह भाषाई संस्कृति पर हमला है, जिसका संगठित बहिष्कार आवश्यक है। अनेक फर्जी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विदेशी नामों की आड़ में भारत के भीतर ही संचालित हो रहे हैं। इन आयोजनों का एक ही उद्देश्य होता है – नाम की आड़ में पैसा कमाना और साहित्यिक गंभीरता का शोषण करना।

साहित्य को साधना ही रहने दो, सौदा मत बनाओ

सच्चा साहित्यकार पुरस्कार के लिए नहीं, समाज के लिए लिखता है। वह पुरस्कार के पीछे नहीं भागता, पुरस्कार उसकी साधना के पीछे भागते हैं। आज जरूरत है ऐसे छलछंद को उजागर करने की, जो साहित्य को सिर्फ एक ₹सेल्फी इवेंट₹ बना रहे हैं। ₹पुरस्कारों की गारंटी₹ देने वाले लोग दरअसल साहित्य की आत्मा के हत्यारे हैं। ऐसे पुरस्कारों से न केवल साहित्यिक गरिमा घटती है, बल्कि युवा लेखकों को एक गलत प्रेरणा मिलती है – कि रचना से अधिक महत्वपूर्ण है, उसकी मार्केटिंग और भुगतान। समाज को सजग बनाइए, बहिष्कार कीजिए। अब समय आ गया है कि हम ऐसे आयोजनों का बहिष्कार करें, पैसे लेकर पुरस्कार बेचने वालों का सामाजिक पदार्फाश करें, सोशल मीडिया और पत्रि-ाकाओं में इनके नाम उजागर करें, सच्चे साहित्यकारों और पाठकों के बीच चेतना फैलाएं, साहित्य को आत्मा की अभिव्यक्ति बनाए रखें, उसकी बोली न लगने दें।

नकली पुरस्कारों का जाल कैसे पहचानें?

पुरस्कार पाने से पहले नामांकन शुल्क या सहयोग राशि मांगी जाए तो सतर्क हो जाइए। जिन आयोजनों के पीछे कोई प्रतिष्ठित संस्थान न हो, केवल फेसबुक पेज या गूगल फॉर्म हो – वे संदिग्ध होते हैं। किसी भी ₹इंटरनेशनल₹ पुरस्कार का आयोजन यदि केवल भारत के छोटे शहरों में हो रहा हो, तो जांच जरूरी है। वेबसाइट पर संस्थापक या निर्णायक मंडल की पारदर्शिता न हो, तो यह लाल झंडी है।

साहित्य बिके नहीं, बचे

हम यह नहीं कह रहे कि पुरस्कार न दिए जाएं – बल्कि पुरस्कार तपस्वी लेखकों की साधना की स्वीकृति होनी चाहिए, न कि किसी वढकभुगतान का रसीद। भाषा की गरिमा बचानी है तो ऐसे नकली संस्थानों से मुक्ति पानी होगी। साहित्य कोई काजल की कोठरी नहीं कि कोई भी चला आए, काजल लगा ले और चला जाए। यह साधना है, सेवा है, संघर्ष है। साहित्य की दुनिया में यह जो बनावटी रोशनी जगाई जा रही है, वह दरअसल एक अंधेरा है – आत्मा से दूर, पैसे के करीब। सच्चे लेखक और पाठक ही मिलकर इस अंधकार को मिटा सकते हैं। अगर साहित्य की आत्मा को जीवित रखना है, तो जरूरी है कि हम ऐसे नकली पुरस्कारों के खिलाफ आवाज उठाएं। यह न केवल लेखन की प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएगा कि पुरस्कार नहीं, सृजन और संवेदना ही साहित्य की असली पूंजी है।

हम साहित्य के उस युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ आत्मा से अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कारों का बायोडेटा हो गया है। आवश्यकता है उस धैर्य, विवेक और विवेचना की जो सच्चे रचनाकार को भीतर से मजबूत करे। ऐसे माहौल में सच्चे साहित्यकारों का मौन अपराध होगा। वे ही यदि इन नकली मंचों को अस्वीकार करेंगे, तभी मूल्यों की पुनर्स्थापना संभव होगी। यह सिर्फ बहिष्कार नहीं, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरूआत है – जहाँ पुरस्कार नहीं, विचारों की गूंज महत्वपूर्ण होगी। साहित्य की साधना को बचाने का यही समय है। आज नहीं बोले, तो कल शायद भाषा ही नहीं बचेगी, जिसके सहारे हम यह लेख लिख रहे हैं।



- डॉ. सत्यवान सौरभ

रूस का विश्वसनीय साझेदार

अमेरिका के मुकाबले रूस भारत का विश्वसनीय साझेदार नजर आता है। रूस भारत के लिए केवल रक्षा साझेदार के साथ रणनीतिक दीर्घकालिक और भरोसेमंद सहयोगी है जो भारत की सुरक्षा, ऊर्जा, कूटनीतिक और वैश्विक प्रभाव के लिए अनिवार्य बना हुआ है। वर्तमान में भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बना रहा है। लेकिन रूस के साथ उसके रणनीतिक संबंध भारत। को रणनीतिक रूप से ज्यादा सक्षम बनाते हैं। रूस भारत के प्रतिद्वंदी देशों से लगती सीमा पर है और यह स्थिति भारत को रणनीतिक बढ़त देती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत अमेरिका की साझेदारी से भारत के रणनीतिक स्वायत्तता बाधित हुई है। किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति उसके पड़ोसी उसकी सीमाएं संसाधन प्राकृतिक बाधाएं और स्थानीय चुनौति स्थाई होती है। चुनौतियां स्थायी होती हैं। देश अपनी भौगोलिक सीमाओं को इतिहास, कुटनीति या युद्ध के माध्यम से थोड़ा बहुत बदल सकता है। अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता। भारत की रणनीतिक और सुरक्षा नीति को चीन और पाकिस्तान जैसे दो पड़ोसियों के खतरे को ध्यान में रख कर ही बनाना पड़ ता है। ट्रंप आर्थिक प्रतिबद्धताओं के सहारे आइजनहावर और ओबामा को झुटला रहे हैं। भारत को समझना होगा कि ट्रंप 'प्रतिद्वंदिता से दबाव में आते हैं। वे चीन के दबाव में आए जबकि यूरोप और भारत जैसे मित्र देशों से उनका कुटनीतिक व्यवहार बेहद असंगत रहा है। जाहिर है भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए रूस जैसे साझेदार की सदा आवश्यकता है-के प्रति लचीले रहने की कुटनीति को फिलहाल नकारने का जोखिम भारत को उठाना ही होगा।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोधारी कुटनीतिक एक अत्यंत व्यवहारिक और प्रभावी उपकरण माना जाता है। विशेषकर तब जब कोई देश अपने हितों को बहुपक्षीय रूप से सुरक्षित करना चाहता है। यह नीति-केवल रणनीतिक लाभ दे सकती है बल्कि विश्वमंच पर एक देश की स्थिति को भी मजबूत भी कर सकती है। भारत ने आर्थिक और सुरक्षा संयोजन में सामंजस्य अपना कर पिछले कुछ वर्षों में बहुपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से मची अराजकता पर कड़ी प्रतिक्रिया से परहेज किया, वहीं युक्रेन पर रूस के हमले से उपजी परिस्थितियों में भारतीयों को सुरक्षित निकालने को कूटनीतिक तक सीमित कर दिया। इस वर्ष की शुरूआत में ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को बेड़ियों से जकड कर अपने-अपने देश भेजा तो कोलंबिया जैसे छोटे से देश ने अपने नागरिकों को वापस भेजने के तरीके पर खुल कर विरोध किया कहीं भारत ने इसे वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया बताकर स्वीकारकर लिया। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से लेकर भारत में उद्योग न लगाने की उनकी सार्वजनिक बयानबाजी ने भारत को विचलित ही किया है। डेढ़ दशक में भारत ने बड़ी संख्या में अमेरिका से सैन्य उपकरणों को खरीदने की शुरूआत की है। भारत अमेरिका का एकऔपचारिक सैन्य सहयोगी नहीं था लेकिन इसके बावजूद उसे अमेरिका की किसी भी इंडो-पैसिफिक रणनीति का आधार बनाया गया और भारत में इसे स्वीकार भी किया। क्वाड चीन न की चुनौती का सीधा मुकाबला करने की एक बड़ी योजना की ओर ले जाया गया। भारत और अमेरिकी संबंधों में गहरे अविश्वास के बाद भी चीन को लेकर दोनों देशों में आपसी साझेदारी को जरूरत को महसूस किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों से भारत और अमेरिका मेरिका के के. संबंध मजबूत हुए है और इसका असर रूस की नीतियों पर देखने को मिल रहा है। किसी दौर में भारत का विश्वास बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को पूर्णरूपेण नजर अंदाज करने की रूस नीति में उदारता देखी जा रही है। रुस के साथ पाकिस्तान के सामरिक संबंध भी बढ़े हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और भू-राजनीतिक मुद्दों पर ऐतिहासिक और मजबूत रिश्ते रहे हैं। भारत ने रूस को हमेशा एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में माना है। यह साझेदरी कई दशकों से कायम है।

डी. आइजनहावर भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। वह दिसंबर, 1959 में दोनों देशों के बीच आश्चर्यजनक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्र पति बने थे। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका भारत को चीनी कम्युनिस्ट आक्रामकता का सामना करने में मदद करेगा। उनकी कुटनीति में स्पष्ट था कि भारत अमेरिकी मित्रता को उस बिंदु एक स्पष्ट रूप से मजबूत करना था जहां कोई गारंटी आवश्यक नहीं थी। चीन से भारत के 1962 के युद्ध में अमेरिका के बिना शर्त सहयोग के बाद भी भारत ने अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया। उस दौरान वियतनाम में अमेरिकी सैन्य से हस्तक्षेप की भारत में मुखर आलोचना की गई। भारत ने 'वियतनाम में' हो रही हिंसा और अमेरिका के सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए वहां शांति और वार्ता का समर्थन किया। भारत ने माना कि यह सब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ वियतनाम की आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। भारत में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अमेरिका के आक्रामक रुख की आलोचना की। भारत ने उत्तर वियतनाम और वियतनामी जनता के आत्म निर्णय के अधिकार अधिकार का समर्थन किया। 1972 में भारत में आधिकारिक रूपसे उत्तर वियतनाम को मान्यता दी थी। भारत का रुख उस समय अंतरराष्ट्रीय नैतिकता और शांति के पक्ष में था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की आलोचना का के भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्वतंत्र और नैतिक विदेश नीतिको झलक दिखाई। यह अमेरिका के लिए अप्रत्याशित था लेकिन भारत ने किया।



गंगा दशमी पर गंगा जल स्नान करने का काफी महत्व है

गंगा नदी का प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या कर धरती पर लाकर पुनीत कार्य किया गंगा नदी का अवतरण शुक्ल पक्ष,माह ज्येष्ठ की दशमी तिथि को हुआ इसी से इस दिन को गंगा दशमी कहते हैं कई क्षेत्रों में इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इसके बाद दान-पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पितृ भी संतुष्ट होते हैं। गंगा के घाट पर जाकर पिंडदान, तर्पण, दान, श्राद्ध और दीपदान करना चाहिए। जो गंगा नदी में स्नान करने जा नहीं सकते वे घर पर गंगाजल डाल कर स्नान कर लेंगें तो फल की प्राप्ति होती हैं श्रद्धा और आस्था,विश्वास के साथ की गई पूजा ,स्नान ,दान से सभी पापों से मुक्ति मिलती है यही भाव माँ गंगा जी की आरती करते समय प्रार्थना के रूप में होते है। गंगा नदी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है इसे प्रदूषण मुक्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है गंगा शुद्धिकरण अभियान के तहत इसमें डॉल्फिन मछलियां भी डाली गई हअे इसके अलावा समय -समय पर शासन द्वारा सफाई का ध्यान भी रखा जाता रहा हैं किंतु आगे जाकर कई शहरों



का निकास का पानी नालों के रूप में समाहित होता है इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

माँ गंगा की छोटी धारा का नर्मदा नदी में समाहित होने का उदाहरण इस प्रकार भी मिलता हैं इंदौर से मनावर 127 किमी की दूरी पर मनावर जिला धार के अंतर्गत मनावर से 25 किमी की दरी पर स्थित गांगली गांव स्थित है ये कालांतर में गंगा से गांगली हो गया ये नर्मदा के तट पर स्थित हैं यहाँ पवित्र कुंड विधमान है जिसमे निरंतर गंगा का जल प्रवाहित होता रहता हैं इस जल की पुष्टि गंगा नदी के जल से की गई जिसको हूबहू जल का होना पाया गया ये जल बहकर नर्मदा के जल में मध्य में इसे सातमात्रा के नाम से भी पुकारा जाने लगा यहाँ माँ गंगा और नर्मदा का मिलन होता हैं यहाँ शिवलिंग भी है जो नंदिकेश्वर के नाम से जाना जाता हैं प्राचीन स्थान का पुराण(स्कंध पुराण के रेवाखंड और शिव पुराण)में लेख हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने होशंगाबाद जिले के सेमरी हरचंद गाँव में कथा वाचन के दौरान मनावर का के नाम का उल्लेख किया था यहाँ दशमी को भव्य मेला भी लगता हैं गंगा दशहरे पर भारी भीड़ रहती हैं ये स्थल सरदार सरोवर के डूब क्षेत्र में आने से जब पानी नहीं रहता तब दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सुलभ होते हैं यहाँ देश के सभी प्रांतो से गूगल मेप के जरिये स्थान खोज कर दर्शन का लाभ लेते हैं यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हैं एक सिंघाना गणपुर होकर एवं एक मनावर से पक्का डामर एवं सीमेंट रोड से सेमल्दा रोड़ पर वायल, पचखेड़ा होकर करोली फाटा आता हैं वहाँ पर क्रांतिकारी टंटिया मामा की प्रतिमा से करोली फाटा से पिपलाज,के आगे से ग्राम बीजाबयड़ी से टर्न होकर मात्र २ किमी की दूरी पर गांगली (साततलाई)में गंगा कुंड निर्मित है कुंड में ऊपर से जाली लगी है ताकि कोई उसमे ना गिरें कुंड में दूसरी और स्नान हेतु पेढ़िया बनी हुई हैं ग्राम का नाम साततलाई में सात तलाई है जिसमे से दो तलाई में पानी भरा हुआ हैं उसके समीप प्राचीन शिव मंदिर हैं और उसी क्षेत्र में जागोद, बागोद दो शिव मंदिर है।जहाँ शुद्ध घी का भंडारा डेढ़ वर्ष तक चला था।दर्शनीय स्थल में माँ गंगा का माँ नर्मदा के जल में विलय होने का स्नान एवं दर्शन लाभ अवश्य लेना चाहिएे गंगा दशहरे के दिन धार्मिक मेला लगता है।



संजय वर्मा 'दृष्टि'

विकास की अंधी दौड़ और प्रकृति का विनाश

हर साल पूरे विश्व में पांच जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस पर्यावरण के संरक्षण के लिए शपथ लेने का दिन है। सभी लोगों को आज के दिन इस प्रकृति और पर्यावरण को सहेजने की जिम्मेदारी लेनी चाहिये। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस पर्यावरण के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनैतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए मनाया जाता है। जब से इस दिवस को सिर्फ मनाया जा रहा है तबसे इसके मनाए जाने को दिखाया या जताया जा रहा है तभी से लगातार पूरे विश्व में पर्यावरण की खुद की सेहत बिगड़ती जा रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि आज जब ये विश्व पर्यावरण दिवस को मनाए जाने की खानापूर्ति की जा रही है। तो प्रकृति भी पिछले कुछ वर्षों से धरती के अलग अलग भूभाग पर, कहीं ज्वालामुखी फटने के रूप में, तो कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं चक्रवात और कहीं ऐसे ही किसी प्रलय के रूप में इस बात का ईशारा भी कर रही है कि अब विश्व समाज को इन पर्यावरण दिवस को मनाए जाने जैसे दिखावों से आगे बढ़ कर कुछ सार्थक करना होगा। विश्व के बडे-बडे विकसित देश और उनका विकसित समाज जहां प्र-कृति के हर संताप से दूर इसके प्रति घोर संवेदनहीन होकर मानव जनित वो तमाम सुविधाएं उठाते हुए स्वार्थी और उपभोगी होकर जीवन बिता रहा है जो पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहे हैं। वहीं विक-ासशील देश भी विकसित बनने की होड में कुछ-कुछ उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं। जो कि पर्यावरण और धरती के लिए लिए घातक सिद्ध हो रहा है।

हम सभी ने इस कोरोना महामारी में देखा कि न जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राण गवाए हैं, इस ऑक्सीजन के अभाव में न जाने कितने परिवार उजाड़ गए, हजारों लोगों ने अपनों को खोया है; ये सब मानव द्वारा प्रकृति और पर्यावरण से की गयी छेड़छाड़ का ही नतीजा है। मानव जाति ने जगह-जगह से प्रकृति का सत्यानाश किया है। इस धरा से पेड़-पौधों को नष्ट किया है। पहाड़ों और ग्लेशियर्स के साथ छेड़छाड़ की है। नदियों के मूल बहाव को रोका है, कई जगह तो इस धरती पर नदियां नाला बनकर रह गयी हैं। नदियों में इंसानी जाति ने इतना प्रदूषण और गन्दगी उड़ेली है कि इससे कई बड़ी-बड़ी नदियां अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। अगर हम प्रकृति की सांसें रोकेंगे तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी ही। जितना इंसानी जाति ने प्रकृति के साथ गलत किया है, अगर उसका एक प्रतिशत भी प्रकृति हमसे बदला लेती है तो इस धरती से इंसान का नामोनिशान मिट जाएगा। जितना क्रूर हम प्रकृति और पर्यावरण के लिए हुए हैं अगर जिस दिन प्रकृति ने अपनी क्रूरता दिखाई उस दिन इस धरती पर प्रलय होगी। इसलिए जरूरी है हम प्रकृति और पर्यावरण की मूलता को नष्ट करने की जगह उसका संरक्षण करें, नहीं तो अभी ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपने प्राण गवाए हैं; आने वाले दिनों में पीने के पानी की कमी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमने ऑक्सीजन तो कृत्रिम बना ली लेकिन पीने के पानी को बनाने की कोई कृत्रिम तकनीक नहीं है। इसलिए समय रहते हमें प्रकृति की ताकत को समझना होगा नहीं तो बहुत देर हो जायेगी। हमें ये भी समझना होगा कि हम प्रकृति के स्वरुप को अपने हिसाब से नहीं बदल सकते, अगर हमने अपने हिसाब से प्रकृति और पर्यावरण के स्वरुप को बदलने का प्रयास किया तो यह आने वाली पीढ़ियों और इस धरती पर रहने वाली मानव जाति और करोड़ों जीव-जंतुओं, पक्षियों के लिए नुकसानदेह होगा।

वैज्ञानिकों के अनुसार अगर धरती का तापमान 2 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो धरती की जलवायु में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जिसके असर से समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ना, बाढ़, जमीन धंसने, सूखा, जंगलों में आग जैसी आपदाएं बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक इसके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को जिम्मेदार मानते हैं। ये गैस बिजली उत्पादन, गाड़ियाँ, फैक्टरी और बाकी कई वजहों से पैदा होती हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका विश्व में कार्बन का उत्सर्जन करता है, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। अगर विश्व के ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश कॉर्बन उत्सर्जन में आने वाले समय में कटौती करते हैं तो यह विश्व के पर्यावरण और जलवायु के लिए निश्चित ही सुखद होगा। अगर बात भारत के वायु प्रदूषण की करी जाये तो आज भारत देश के बड़े-बड़े शहरों में अनगिनत जेनरेटर धूंआ उगल रहे हैं, वाहनों से निकलने वाली गैस, कारखानों और विद्युत गृह की चिमनियों तथा स्वचालित मोटरगाड़ियों में विभिन्न इंधनों के पूर्ण और अपूर्ण दहन भी प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, और पर्यावरण की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार जहरीली गैसों कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड और अन्य गैसों सहित एसपीएम, आरपीएम, सीसा, बेंजीन और अन्य खतरनाक जहरीले तत्वों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। जो कि मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का। कई राज्यों में इस समस्या का कारण किसानों द्वारा फसल जलाना भी है। साथ ही साथ अधिक पटाखों का जलाना भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आज जरूरत है केंद्र और प्रदेश सरकारों को वायु-प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य-जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। और लोगों को विज्ञापन या अन्य माध्यम से वायु प्रदूषण व



अन्य प्रदूषण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना है कि इस पर अमल नहीं हो रहा है। सरकार को किसानों को फसलों को न जलाने के लिए जागरूक करना चाहिए। किसानों को फसलों (तूरियों) को जलाने की जगह चारे, खाद बनाने या अन्य प्रयोग के लिए जागरूक करना चाहिए। ज्यादा प्रदूषण करने वाले पटाखों पर भी सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। हमारी सरकार को ईंधन की गुणवत्ता को बढ़ाकर पॉल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल करने पर जोर देना चाहिए। जिससे उसमें उपलब्ध जरूरी तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक न हो तथा उत्सर्जन निर्धारित मानक अनुसार रहे। ईंधन से ज्यादा प्रदूषण करने वाले तत्वों की कमी कैसे की जाए इस पर भी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। कम पॉल्यूशन करने वाले ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी इत्यादि का अधिक प्रयोग करने लिए लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ यातायात प्रणाली में सुधार करना चाहिए। आज सरकारों को उत्सर्जन मानकों का भी सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है। अगर लोग साइलेंसर पर केटालिक कनवर्टर लगाएं तो भी वाहन द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सरकार को लोगों को वाहनों का समय पर मेंटीनेंस कराने के लिए जागरूक करना चाहिए। जागरूक लोगों को स्वतः ही अपने वाहनों का मेंटीनेंस करना चाहिए। जब प्रदूषण स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाता है, और तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि फेफड़ों में संक्रमण व आंख, नाक व गले में कई तरह की बीमारियों और ब्लड कैंसर जैसी तमाम घातक बीमारियों को जन्म देता है। अगर क्षेत्र में वायु प्रदूषण मानकों से ज्यादा है तो लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जिससे कि वायु में मिले हुए घातक तत्वों और गैसों से काफी हद तक बचा जा सके।

आज प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकारों को नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। अगर लोग देश में निजी वाहनों कि जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें तो वायु प्रदूषण को काफी नियन्त्रित किया जा सकता है, इसके लिए लोगों को खुद सोचना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर जुमार्ने का प्रावधान हो। तभी देश में वायु प्रदूषण से निपटा जा सकता है। अगर देश में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए कानूनों का सख्ती से पालन हो तो वायु प्रदूषण जैसी समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है। इससे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी।

आज यदि धरती के स्वरूप को गौर से देखा जाए तो साफ पता चल जाता है कि आज नदियां , पर्वत, समुद्र, पेड़, और भूमि तक लगातार क्षरण की अवस्था में हैं। और ये भी अब सबको स्पष्ट दिख रहा है कि आज कोई भी देश, कोई भी सरकार, कोई भी समाज इनके लिए उतना गंभीर नहीं है जितने की जरूरत है। बेशक लंदन की टेम्स नदी को साफ करके उसे पुनर्जीवन प्रदान करने जैसे प्रशंसनीय और अनुकरणीय प्रयास भी हो रहे हैं मगर ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। ऐसे अनुकरणीय प्रयास भारत में भी हो सकते हैं जिसके द्वारा भारत की प्रदूषित नदियों को निर्मल और अविरल बनाया जा सकता है। चाहे वो गंगा नदी हो या यमुना नदी इस सबके लिए जरूरी है दृढ इच्छा शक्ति की जो कि भारतीय सरकार के साथ-साथ भारत के हर इंसान में होनी चाहिए।

आज जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी के ऊपर से हरा आवरण लगातार घटता जा रहा है जो पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दे रहा है। पर्यावरणीय संतुलन के लिए वनों का संरक्षण और नदियों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि धरती को बचाने की मुहिम को इंसान को बचाने के मिशन के रूप में बदलना होगा क्योंकि मनुष्य और पर्यावरण का परस्पर गहरा संबंध है। पर्यावरण यदि प्रदूषित हुआ, तो इसका प्रभाव मनुष्य पर पड़ेगा और मनुष्य का स्वास्थ्य बिगडेगा और जनस्वास्थ्य को शत-प्रतिशत उपलब्ध करा सकना किसी भी प्रकार संभव न हो सकेगा। सभी जानतें हैं कि इंसान बडे बडे पर्वत नहीं खडे कर सकता, बेशक चाह कर भी नए साफ समुद्र नहीं बनाए जा सकते; किंतु ये प्रयास तो किया ही जा सकता है कि इन्हें दोबारा से जीवन प्रदान करने के लिए संजीदगी से प्रयास किया जाए। भारत में तो हाल और भी बुरा है। जिस देश को प्रकृति ने अपने हर अनमोल रत्न, पेड, जंगल, धूप, बारिश, नदी, पहाड, उर्वर मिट्टी से नवाजा हो, और उसको मुकुट के सामान हिमालय पर्वत दिया हो और हार के समान गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियाँ दी हों यदि वो भी इसका महत्व न समझते हुए इसके नाश में लीन हो जाए तो इससे अधिक अफसोस की बात और क्या हो सकती है। आज ये सब पर्यावरणीय समस्याएं विश्व केसामने मुंह बाए खड़ी हैं। विकास की अंधी दौड़ के पीछे मानव प्रकृति का नाश करने लगा है। सब कुछ पाने की लालसा में वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगा है। प्रकृति तभी तक साथ देती है, जब तक उसके नियमों के मुताबिक उससे लिया जाए। इसके लिए सबसे सरल उपाय है कि पूरी धरती को हरा भरा कर दिया जाए। इतनी अधिक मात्रा में धरती पर पेड़ों को लगाया जाए कि धरती पर इंसान द्वारा किया जा रहा सारा विष वमन वे वृक्ष अपने भीतर सोख सकें और पर्यावरण को भी सबल बनाने की उर्जा प्रदान कर सकें। अच्छा होगा यदि कुछ छोटे-छोटे कदम उठा कर लोगों को धरती के प्रति, पेड़-पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बडे-बडे सम्मेलनों, आशावादी समझौतों आदि से अच्छा तो ये होगा कि इन उपायों पर काम किया जाए। लोगों को बताया समझाया और महसूस कराया जाए कि पेड बचेंगे, तो धरती बचेगी, धरती बचेगी, तो इंसान बचेगा। सरकार यदि ऐसे कुछ उपाय अपनाए तो परिणाम सुखद आएंगे।

लू से 700 मौतें हो गई, राजनीतिक दलों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी

देश में आम लोगों की जिन्दगी कोई मोल नहीं है। कम से कम सरकारों और राजनीतिक दलों की नजर में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। मुद्दा यदि वोट बैंक से जुड़ा हुआ हो, तभी राजनीतिक दल कुछ गंभीरता बेशक दिखा लें किन्तु लोगों के जीवन-मरण जैसे मुद्दों से लगता यही है कि उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो अदालतों को मौसम की मार से होने वाली मौतें रोकने के लिए सरकारों को दिशा-निर्देश नहीं देने पड़ते। आश्चर्य की बात यह है कि प्रतिकूल मौसम से आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों की सरकारों की है, किन्तु यह काम भी अब अदालतों को करना पड़ रहा है। इससे सवाल खड़ा होता है कि आखिर सरकारों की जरूरत कितनी सीमित रह गई है।

हीटवेव से 700 से ज्यादा मौतों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि इतने बड़े मौसमी संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या तैयारी की जा रही है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गृह मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने दाखिल की। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की है कि सरकार को गर्मी की चेतावनी देने वाली प्रणाली, हीटवेव की पहले से जानकारी देने की व्यवस्था, और 24 घंटे काम करने वाली राहत हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं लागू करने के निर्देश दिए जाएं।

याचिका में यह भी बताया गया है कि 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हीटवेव से निपटने के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए थे, लेकिन कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक उस पर काम ही नहीं किया। याचिका में यह भी जिक्र है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की आपदा से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैये पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पिछले साल दिए गए अदालत के निदेर्शों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून के शासन पर सवाल उठाता है। अधिकारी स्वयं को कानून से ऊपर मान रहे हैं, लेकिन कोर्ट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इंसानों से जानवरों जैसा बर्ताव नहीं हो सकता और न जान बचाने के लिए धन की कमी का बहाना चल सकता। कोर्ट ने मुख्य सचिव से अदालती आदेशों की पालना के लिए समन्वय समिति बनाने और लू से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया, वहीं केन्द्रीय गृह मंत्रालय, मुख्य सचिव व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केन्द्र व राज्य सरकार के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भागों में गर्मियों के दौरान पड़ने वाली लू के मद्देनजर 11 राज्यों से कहा है कि वे कमजोर लोगों, खासकर आर्थिक रूप से



कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और बेघर लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाएं, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू के कारण 3,798 लोगों की मौत के बारे में एनसीआरबी के आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए आयोग ने एकीकृत और समावेशी उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, कार्य घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है।

भारत में वर्ष 2001 से 2019 के बीच हीटवेव यानी लू से करीब 20हजार लोगों की मौत हुई है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि पुरुषों में लू से होने वाली मौतों की आशंका ज्यादा पाई गई। एक और हालिया अध्ययन में यह बताया गया है कि हीटवेव से होने वाली मौतें जातीय आधार पर भी बंटी हुई हैं। भारत में हाशिए पर मौजूद समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मौतें, अन्य समुदायों की तुलना में, लू से कहीं ज्यादा हुईं। अध्ययन करने वाले शोधकताओं का कहना है कि यह एक तरह की 'थर्मल इनजस्टिस' (गर्मी से जुड़ा अन्याय) की स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की 2021 की एक रिपोर्ट जैसी कई रिपोर्टों ने चेतावनी दी है कि भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में आने वाले वर्षों में और भी एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे कि हीटवेव, देखने को मिलेंगी। हर साल गर्मी के रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं।



भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, फरवरी 2025 भारत में बीते 125 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा है। टीम ने पाया कि 2001 से 2019 के बीच भारत में हीटस्ट्रोक से 19,693 मौतें और अत्यधिक ठंड से 15,197 मौतें दर्ज की गईं। हालांकि, यह संख्या असल आंकड़ों से कम हो सकती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने से होने वाली मौतों की रिपोटिंग पर्याप्त रूप से नहीं होती। यह बात 29 अप्रैल को प्रकाशित एक अध्ययन में कही गई है, जो वैज्ञानिक पत्रिका 'टेम्परेचर' में प्रकाशित हुआ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि हीटस्ट्रोक से मरने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक थी; इस अवधि में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मौतें तीन से पांच गुना ज्यादा थीं। इतना ही नहीं लू जैसी आपदा के अलावा बाढ़, अतिवृष्टि और बिजली गिरने जैसी आपदाओं में हर साल हजारों लोग काल कलवित हो जाते हैं। ऐसे मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडे में शामिल नहीं हैं। कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करना तो दूर बल्कि यह दावा तक नहीं करता कि किसी भी व्यक्ति की मौत ऐसे प्राकृतिक कारणों से नहीं होगी। इससे साफ जाहिर है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में ऐसी मौतों की रोकथाम के गंभीर प्रयास करना या इसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करना नहीं है। कारण स्पष्ट है इससे दलों के वोट बैंक में इजाफा नहीं होता। ऐसे मुद्दों के लिए सत्तारुढ़ दलों के नेताओं से अधिक नौकरशाहों को जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। इनकी जवाबदेयी के लिए जब तक कानून के तहत दंड का प्रावधान नहीं होगा, तब हर साल प्राकृतिक आपदाओं लोगों की मौत होती रहेंगी।



मैं लिखता रहा

मैं लिखता रहा
लिख-लिख मिटाता रहा ।
वक्त ने सताया
मैं सहता रहा
काल के माथ पर
लिखता रहा
लिख- लिख मिटाता रहा ।
कभी भाग्य
कभी समय को दोष देता रहा
मैं कर्मपथ पर चला
कभी गिरा
कभी उठा
और चलता रहा
मैं लिखता रहा
लिख- लिख मिटाता रहा ।

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
गांव रिहावली, डाक घर तारौली गूजर,
फतेहाबाद, आगरा,

भारत में 1881 से 1931 के बीच की गई जनगणना के दौरान सभी जातियों की गणना की गई थी, लेकिन 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना नहीं कराने का निर्णय लिया था।



जातिगत जनगणना के निर्णय के बाद तमाम तरह के सुझाव दे रहे लोग क्या यह इतिहास जानते हैं?

मोदी सरकार ने जबसे देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है तबसे हर रोज कोई ना कोई राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस संबंध में सुझाव दे रहा है। ताजा सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिया है। उन्होंने आग्रह किया है कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल का उपयोग करना चाहिए। इसी तरह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोई कह रहा है कि पहले इस वर्ग की गणना करा लो तो कोई कह रहा है कि पहले उस वर्ग की गणना करा लो। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले किसकी गणना होनी चाहिए? यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या देश में जनगणना और जातिगत जनगणना का इतिहास लोग जानते भी हैं?

इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए आइये कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। आजादी से पहले भारत में 1881 से 1931 के बीच की गई जनगणना के दौरान सभी जातियों की गणना की गई थी, लेकिन 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना नहीं कराने का निर्णय लिया था। एक दशक बाद 1961 में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वे चाहें तो अपने स्तर पर सर्वेक्षण कराएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूचियां तैयार करें। छह दशक से अधिक समय बाद अब, विभिन्न धड़ों एवं अलग-अलग राजनीतिक दलों की मांगों के बाद सरकार ने अगली राष्ट्रव्यापी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। हम आपको बता दें कि आखिरी बार देश भर में जाति गणना 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईस-ीसी) के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य परिवारों और व्यक्तियों की जाति सहित उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करना था।



जाति गणना क्या है?

जाति गणना में राष्ट्रीय जनगणना कवायद के दौरान व्यक्तियों की जातियों पर आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह शामिल है। भारत में, जहां जाति ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिशीलता को आकार दिया है, ऐसे आंक- ड़े जनसांख्यिकीय वितरण, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल विभिन्न कार्यक्रमों में आरक्षण और सामाजिक न्याय पर नीतियों को सूचित करने के लिए किया जा सकता है।

भारत में जाति गणना का एक लंबा इतिहास है:

ब्रिटिश भारत (1881-1931): ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1881 और 1931 के बीच हर दशक में आयोजित जनगणना में जाति गणना को शामिल किया। इन सर्वेक्षणों ने विस्तृत जनसांख्यिकीय आंकड़े प्रदान करते हुए जनसंख्या को जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया। यह कदम आंशिक रूप से भारत की जटिल सामाजिक संरचना को समझने और उस पर शासन करने की औपनिवेशिक आवश्यकता से प्रेरित था।

स्वतंत्रता के बाद का बदलाव (1951): 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना ने एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर जाति गणना को बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित था कि जाति पर ध्यान केंद्रित करने से विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

1961 का निर्देश: एक दशक बाद, 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य-विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए अपने स्तर से सर्वेक्षण कराने की अनुमति दी। यह कदम एससी और एसटी से परे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए कल्याणकारी कदमों की मांग के जवाब में था। हालांकि, कोई राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना नहीं की गई थी।

जाति जनगणना कैसे एक राजनीतिक मुद्दा बन गई?

मंडल आयोग (1980): केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मंडल आयोग की सिफारिश ने जाति को फिर से राजनीतिक चर्चा में ला दिया। जाति संबंधी व्यापक आंकड़ों की कमी ने ओबीसी आबादी की सही पहचान और मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे जाति जनगणना की मांग बढ़ गई।

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011: वर्ष 2011 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करवाई, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालांकि, एसईसीसी 2011 के आंकड़ों को कभी भी पूरी तरह से जारी या उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण विपक्षी दलों और जाति-आधारित संगठनों ने इसकी आलोचना की।

राज्य स्तरीय पहल: राष्ट्रीय जातिगत जनगणना के अभाव में, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने हाल के वर्षों में अपने-अपने यहां जाति सर्वेक्षण कराए हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट आरक्षण नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए आंकड़े एकत्र करना था। 2023 में बिहार के जाति सर्वेक्षण से पता चला कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) राज्य की आबादी का 63 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं।

जाति जनगणना क्यों मायने रखती है?

जाति जनगणना एक जनसांख्यिकीय कवायद से कहीं अधिक है; यह गहरे सामाजिक निहितार्थों वाला राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है: जनगणना में जाति को शामिल करने से आरक्षण नीतियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय पहल पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। यह चुनावी रणनीतियों को भी नया रूप दे सकता है, क्योंकि पार्टियां विभिन्न जाति समूहों से समर्थन पाने की होड़ में लगी रहती हैं। भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच जाति, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्थिति की संरचनात्मक असमानताओं से प्रभावित होती है। इन असमानताओं को उजागर करने और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है जो वास्तव में समतामूलक और समावेशी हों।

इसके अलावा, सटीक जातिगत आंकड़े मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसी विभिन्न नीतियों को तैयार करने में मदद कर सकता है। कई लोग हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना को जरूरी मानते हैं, लेकिन लोग यह भी चेतावनी देते हैं कि इससे जातिगत पहचान मजबूत हो सकती है और विभाजन गहरा सकता है।

आगे क्या होने वाला है?

यह घोषणा व्यापक जातिगत गणना के 70 से अधिक वर्षों के प्रतिरोध के बाद एक प्रमुख नीतिगत मोड़ है, लेकिन आंकड़ों को कैसे एकत्रित, वर्गीकृत और इस्तेमाल किया जाएगा, यह देखना अभी बाकी है। आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने से शासन, चुनावी राजनीति और असमानता से निपटने के प्रयास पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि यह प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी।

सरसंघचालक की पहल से बदल सकती है जातिवाद की तस्वीर

राजनीतिक उद्देश्य के निहितार्थ ही सही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) ने अगड़े, पिछड़े और अंतरजातीय विवाह की शुरूआत करा कर देश में जातिवाद के दुष्चक्र को तोडने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की है। देश की तरक्की और एकता-अखंडता का अक्षुण रखने में समाज का जाति और उपजातियों में बंटा होना प्रमुख बाधा है। सदियों से चली आ रही जातिवाद की जड़े इतनी गहरी हैं कि इसको समूल उखाड़ कर देश का नवनिर्माण करना किसी दुष्कर चुनौती से कम नहीं है। सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने वाराणसी में पिता बनकर 125 लड़कियों का कन्यादान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवाह समाज निर्माण का आधार है। इस भव्य समारोह में सवर्ण, दलित और पिछड़े समाज के 125 जोड़ों का सामूहिक विवाह वैदिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इससे पहले भावगत और संघ परिवार कई बार हिन्दुओं की एकता की दुहाई दे चुके हैं। इस एकता में सबसे बड़ी बाधा जातिवाद है। आरएसएस की समझाइश के बावजूद जातिवाद का असर कम नहीं हुआ। इसके लिए सामूहिक विवाह की शुरूआत करा कर पहल की गई। जातिवाद तोड़ने की दिशा में यह महज एक कदम है, जबकि फासला सैकड़ों मील का है। यह संभव है कि आरएसएस आगे भी इसी तरह की पहल को जारी रखे। एक-एक कदम बढ़ा कर ही शायद एक दिन बगैर जाति के राष्ट्रवाद का सपना साकार हो सके। इसमें अभी भी बाधाओं की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस और भाजपा का इसमें कोई छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा नहीं है।

राजनीतिक सिद्धि के बावजूद यह प्रयास सकारात्मक ही माना जाएगा। भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना कर यह साबित किया भी किया है वोट बैंक की मौजूदा जातिवाद की राजनीति के बावजूद विकास की बुनियाद पर सत्ता प्राप्त की जा सकती है। इसका बड़ा उदाहरण राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन में भी देखने को मिला। इससे पहले भाजपा भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह राज्यों में बड़े नेताओं की बंधक बनी हुई थी। इन नेताओं की उपेक्षा करके चुनाव जीतना और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना संभव नहीं था, किन्तु भाजपा ने यह भ्रम तोड़ दिया। इसके साथ जाति आधारित नेताओं के पार्टी को ब्लेकमेल किए जाने की परंपरा को भी पछाड़ दिया। हालांकि दूसरे राजनीतिक दलों में ऐसा करने का साहस अभी तक नहीं है, विपक्षी दलों में इसकी छटपटाहट जरूर नजर आती है।



अंतरजातीय विवाह करने पर अक्सर जातिवाद का कहर न सिर्फ नवविवाहितों को बल्कि उनके पूरे परिवार तक को झेलना पड़ता है। भारत के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग आम हैं। भारत में ऑनर किलिंग तब होती है जब कोई जोड़ा अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करता है। करनाल की एक सत्र अदालत ने खाप पंचायत के आदेश के विरुद्ध विवाह करने वाले एक युवा जोड़े की हत्या के लिए पांच लोगों को पहली बार मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसने खाप पंचायत के एक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने विवाह को अवैध घोषित कर दिया था और हत्या के समय वह मौजूद था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और आठ राज्यों को नोटिस जारी कर ऑनर किलिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी। सरकार ने सतर्कतापूर्ण रुख अपनाते हुए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करने और खाप पंचायतों (जाति आधारित संविधानेतर निकाय) पर लगाम लगाने के पूर्व कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। हालांकि, इसने राज्यों से परामर्श करने और एक विशेष कानून बनाने की गुंजाइश पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन करने का फैसला किया, जो ऑनर किलिंग को एक सामाजिक बुराई के रूप में मानेगा। प्रस्तावित ऑनर किलिंग कानून को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो मौजूदा कानून ऑनर किलिंग को रोकने के लिए पर्याप्त हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ऑनर किलिंग की समस्या से निपटने के लिए अधिक सख्त और विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता है। भारत में 2019 और 2020 में ऑनर किलिंग की संख्या 25-25 थी और 2021 में 33 थी।

दलित ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क (डीएचआरडीनेट) द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर विमेन लीडर्स (एनसीडब्ल्यू) के सहयोग से प्रकाशित एक रिपोर्ट में सात राज्यों- हरियाणा, गुजरात, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश- में जाति आधारित ऑनर किलिंग की तस्वीर सामने रखी थी। रिपोर्ट में 2012 से 2021 के बीच के 24 मामलों पर नजर डाली गई है और लगभग सभी मामलों में पीड़ितों/सर्वाइवर्स को रिश्ते या शादी का विरोध करने वाले परिजनों के हाथों अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में पाया गया कि कई मामलों में केवल एक व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों पर भी हमला किया गया। हरियाणा के एक मामले में अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले एक पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसमें तमिलनाडु में एक अन्य मामले में एक जोड़ा ऐसा था, जो अंतरजातीय संबंध में था और साथ घर छोड़कर कहीं जाकर छिप गया था। चूंकि वे मिले नहीं, इसलिए लड़की के परिवार वालों ने बदला लेने के लिए लड़के की बहन का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुरुष अनुसूचित जाति से और महिला थेवर जाति की थी। भारत में सम्मान आधारित अपराधों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। इन मामलों की आईपीसी के मौजूदा प्रावधानों के तहत जांच की जाती है, और जब पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखता है तो एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू होता है।

वर्ष 2012 में भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि विशेष रूप से 'ऑनर क्राइम' के लिए एक अलग कानून बनाया जाए। रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर एक विधेयक ड्राफ्ट भी किया गया और उसमें किसी जोड़े को डराने-धमकाने के अपराधीकरण समेत विशिष्ट कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी। हालांकि, 'किसी भी सांसद ने इस बिल को संसद में पेश नहीं किया।' रिपोर्ट बताती है कि विधि आयोग के किए कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्ष 2018 में, शक्ति वाहिनी बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर किलिंग को एक गंभीर मुद्दे के रूप में मान्यता दी और ऑनर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य एवं पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की। इस खतरे से निपटने के लिए अब तक कुछ गंभीरता दिखाने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। वर्ष 2019 में राजस्थान ने 2012 के विधि आयोग की रिपोर्ट पर आधारित एक विधेयक विधानसभा में पेश किया। इसे अगस्त 2019 में राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया था। हालांकि, यह कानून नहीं बन पाया है क्योंकि इस पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए। जाति आधारित ऐसे सामाजिक बुराईयों से दो तरफा तरीकों से निपटना होगा। कानून में सुरक्षा की गारंटी के साथ अतंरजातीय विवाह संबंधों को प्रोत्साहित करने से देश की तस्वीर बदल सकती है।

अपने कार्यक्रमों में विभिन्न विचारों के महानुभावों को आमंत्रित करने की संघ की परंपरा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबके लिए खुला संगठन है। इसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। कोई भी संघ में आ सकता है। कोई विपरीत विचार का नेता, सामाजिक कार्यकर्ता या विद्वान व्यक्ति जब संघ के कार्यक्रम में शामिल होता है, तब उन लोगों को आश्चर्य होता है, जो संघ को एक क्लोज्ड डोर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। जो संघ को समझते हैं, उन्हें यह सब सहज ही लगता है। इसलिए नागपुर में आयोजित संघ शिक्षावर्ग कार्यकर्ता विकास वर्ग-2 के समापन समारोह में जब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के जनजाति वर्ग के कद्दावर नेता अरविंद नेताम को आमंत्रित किया गया, तब संघ को जाननेवालों को यह सहज ही लगा लेकिन संघ के प्रति संकीर्ण सोच रखनेवाले इस पर न केवल हैरानी व्यक्त कर रहे हैं अपितु वितंडावाद भी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, उनके वितंडावाद की हवा स्वयं जनजातीय नेता अरविंद नेताम ने यह कहकर निकाल दी कि वनवासी समाज की समस्याओं और चुनौतियों को संघ कार्यक्रम के माध्यम से रखने का सुअवसर मुझे मिला है। उन्होंने संघ के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की है कि इस संगठन में चिंतन-मंथन की गहरी परंपरा है। भविष्य में जनजातीय समाज के सामने जो चुनौतियां आनेवाली हैं, उसमें आदिवासी समाज को जो संभालनेवाले और मदद करनेवाले लोग/संगठन हैं, उनमें हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानते हैं। सुप्रसिद्ध जनजातीय नेता अरविंद नेताम श्रीमती इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संघ के कार्यक्रमों में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अंबेडकर और जय प्रकाश नारायण से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी एवं प्रणब मुखर्जी तक शामिल हो चुके हैं। संघ ने कभी किसी से परहेज नहीं किया। संघ अपनी स्थापना के समय से ही सभी प्रकार के मत रखनेवाले विद्वानों से मिलता रहा है और उन्हें अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संवाद में गहरा विश्वास है। वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत कहते हैं कि अगर हम विचारों को एक किला बनाकर उसके अंदर अपने आपको बंद कर लेंगे, तो यह व्यावहारिक नहीं होगा। संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार प्रतिष्ठित राजनेता थे। कांग्रेस, समाजवादी एवं कम्युनिस्ट नेताओं के साथ उनका गहरा परिचय था। संघ का दर्शन कराने के लिए डॉक्टर साहब लगातार विभिन्न विचारों के विद्वान व्यक्तियों एवं सामाजिक-राजनीतिक कार्यकताओं से मिलते थे और उन्हें संघ में आमंत्रित करते थे। वे उस समय की चुनौतियों के संबंध में सबसे विचार-विमर्श करके समाधान के मार्ग तक पहुँचने का प्रयास करते थे। संघ के वर्तमान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर अपनी पुस्तक **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : स्वर्णिम भारत के दिशा-सूत्र** में लिखते हैं कि किसी विषय पर विभिन्न मत हो सकते हैं, किंतु जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग से मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो अवश्य ही समाधान निकलता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1930 के दशक से ही समाज जीवन में सक्रिय लोगों को अपने कार्यक्रमों में बुलाता रहा है। दरअसल, एक और महत्वपूर्ण बात है यह कि संघ को विश्वास है कि जब तक कोई संघ से दूर है, तब तक ही वह संघ का विरोधी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वह संघ के निकट आता है और संघ को जानने-समझने लगता है, तब वह संघ का विरोधी हो ही नहीं सकता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन और लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी संघ के आमंत्रण पर आ चुके हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मानित समाजवादी नेता थे। प्रारंभ में संघ को लेकर उनके विचार आलोचनात्मक थे। लेकिन जब उन्होंने संघ को नजदीक से देखा तब उनके विचार पूरी तरह बदल गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ह्लयदि आरएसएस फ-ासीवादी संगठन है तो जेपी भी फासीवादी हैह्व। प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और संघ के पदाधिकारियों के साथ मित्रतापूर्ण संवाद रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि ह्लमैं संघ का विधिवत सदस्य नहीं हूँ, फिर भी स्वभाव से, परिकल्पना से मैं स्वयंसेवक हूँ। परम पावन दलाई लामा संघ के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, उनका भी कहना है कि मैं संघ का समर्थक हूँ। अनुशासन, देशभक्ति और समाज सेवा के लिए यह संगठन जाना जाता है। वर्ष 1977 में आंध्रप्रदेश में आए चक्रवात के समय स्वयंसेवकों के सेवा कार्यों को देखकर वहां के सर्वोदयी नेता प्रभाकर राव ने तो संघ को नया नाम ही दे दिया था। उनके अनुसार- आरएसएस अर्थात रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस।

संघ के कार्यक्रम में जब भी कोई अन्य विचार का व्यक्ति आया है, तब संघ के कार्यकताओं की ओर से कभी उनका विरोध नहीं हुआ। बल्कि स्वयं को अधिक प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक बतानेवाले लोगों ने ही आमंत्रित महानुभावों को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। जब उनके सब प्रयत्न विफल हो जाते हैं, तब ये लोग आमंत्रित महानुभावों की छवि पर हमला करने लगते हैं। उन्हें छिपा हुआ संघी घोषित कर देते हैं। याद हो, वर्ष 2018 में नागपुर के रेशिमबाग में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग-तृतीय वर्ष के समापन समारोह में जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शामिल होने का समाचार सामने आया, तब कितना हो-हल्ला मचाया गया। प्रणब दा को रोकने के लिए पत्र लिखे गए, आह्वान किए गए। आखिर में प्रणब दा समारोह में पहुँचे और अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर प्रणब दा न केवल आद्य सर-संघचालक डॉ. हेडगेवार के घर (संग्रहालय) गए, बल्कि वहाँ उन्होंने विजिटर बुक में लिखा-मैं आज भारत माँ के महान सपूत डॉ. केबी हेडगेवार के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और दलित नेता दादासाहेब रामकृष्ण सूर्यभान गवई तथा कम्युनिस्ट विचारों वाले जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर भी संघ के कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मीनाक्षीपुरम में कुछ हिंदुओं द्वारा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किए जाने की घटना के बाद श्री गवई ने स्वयं संघ के कार्यक्रम में आने की इच्छा व्यक्त की थी और अपने विचार रखे थे। केरल की पहली कम्युनिस्ट सरकार में मंत्री रहे जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर ने स्थानीय विरोधों के बावजूद तत्कालीन सरसंघचालक से संपर्क किया और बाद में पत्रकारों के सामने अपने विचार रखे थे।

अभी हाल के वर्षों में देखें तो, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, डीआरडीओ के पूर्व डायरेक्टर जनरल विजय सारस्वत, एचसीएल के प्रमुख शिव नाडर, नेपाल के पूर्व सैन्य प्रमुख रुकमंगुड कटवाल जैसे व्यक्तित्व संघ के विजयादशमी उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो चुके हैं। पिछले एक दशक में नागपुर में आयोजित होनेवाले संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में आए प्रमुख महानुभावों में दैनिक पंजाब केसरी के संचालक एवं संपादक अश्वनी कुमार, आदि चुनचुनगिरी मठ (कर्नाटक) के प्रधान पुजारी निर्मलानंदनाथ महास्वामी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्रीश्रीरविशंकर, धर्मस्थल कर्नाटक के धर्माधिकारी पद्मविभूषण डॉ. विरेन्द्र हेगडे, साप्ताहिक वर्तमान (कोलकाता) के संपादक रंतिदेव सेनगुप्त, श्रीरामचंद्र मिशन (हैदराबाद) के अध्यक्ष दाजी उपाख्य कमलेश पटेल, श्रीकाशी महापीठ (वाराणसी) के 1008 जगद्गुरु डॉ. मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी, श्रीसिद्धगिरी संस्थान मठ (कोल्हापुर) के अद्दश्य काड-सिद्धेश्वर स्वामी और श्री क्षेत्र गोदावरी धाम बेट सराला के पीठीधीश श्री रामगिरीजी महाराज प्रमुख हैं। इसके अलावा देशभर में आयोजित संघ शिक्षा वर्गों के कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रमों समाज जीवन के प्रतिष्ठित लोगों को संघ आमंत्रित करता है।

जनरल करिअप्पा ने की संघ कार्य की प्रशंसा

वर्ष 1959 में पूर्व जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा मंगलोर में संघ की एक शाखा के कार्यक्रम में गए थे। वहाँ उन्होंने कहा था कि संघ कार्य मुझे अपने हृदय से प्रिय कार्यों में से है। अगर कोई मुस्लिम इस्लाम की प्रशंसा कर सकता है, तो संघ के हिंदुत्व का अभिमान रखने में गलत क्या है? प्रिय युवा मित्रों, आप किसी भी गलत प्रचार से हतोत्साहित न होते हुए कार्य करो। डॉ. हेडगेवार ने आपके सामने एक स्वार्थरहित कार्य का पवित्र आदर्श रखा है। उसी पर आगे बढ़ो। भारत को आज आप जैसे सेवाभावी कार्यकताओं की ही आवश्यकता है।

संघ के वर्ग एवं शाखा में महात्मा गांधी

वर्ष 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीत शिविर वर्धा में महात्मा गांधी के आश्रम के पास ही लगा था। गांधीजी ने शिविर को देखने इच्छा प्रकट की। वर्धा के संघचालक अप्पाजी जोशी ने शिविर में उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी ने बड़ी बारीकी से शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अप्पाजी से पूछा कि इस शिविर में कितने हरिजन हैं? अप्पाजी ने जवाब दिया- ह्लयह बताना कठिन है, क्योंकि हम सभी को हिंदू के रूप में ही देखते हैं। इतना हमारे लिए पर्याप्त हैह्व। बाद में उनकी भेंट संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार के साथ हुई। संघशिक्षा वर्ग में जाने की यह बात स्वयं महात्मा गांधी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही। 16 सितंबर, 1947 की सुबह दिल्ली में संघ की शाखा पर जाकर महात्मा गांधी ने स्वयंसेवकों से संवाद किया। उन्होंने कहा- ह्लबरसों पहले मैं वर्धा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शिविर में गया था। उस समय इसके संस्थापक हेडगेवार जीवित थे। स्व. जमनालाल बजाज मुझे शिविर में ले गये थे और वहां मैं उन लोगों का कड़ा अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति देखकर अत्यन्त प्रभावित हुआ था। संघ एक सुसंगठित, अनुशासित संस्था है।

संघ शिक्षा वर्ग में डॉ. भीमराव आंबेडकर

समाज को समरसता के सूत्र में पिरोकर उसे संगठित और सशक्त बनाने वाले महानायकों में से एक डॉ. भीमराव आंबेडकर भी संघ के प्रणेता डॉ. हेडगेवार के संपर्क में थे। बाबा साहेब 1937 और 1939 में संघ शिक्षा वर्ग में गए थे। 1937 में करहाड शाखा (महाराष्ट्र) के विजयादशमी उत्सव पर बाबा साहब का भाषण हुआ। इस दौरान वहां 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। जिन्हें देखकर डॉ. आंबेडकर को आश्चर्य तो हुआ ही बल्कि भविष्य के प्रति उनकी आस्था भी बढ़ी। सन- 1939 में एक बार फिर बाबा साहब पुणे के संघ शिक्षा वर्ग के सायंकाल के कार्यक्रम में आए थे। यहाँ उनकी भेंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं तत्कालीन सरसंघचालक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार से हुई। इसी प्रकार, संघ से प्रतिबंध हटाने में डॉ. अंबेडकर का जो सहयोग प्राप्त हुआ, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव गोलवलकर ने सितंबर 1948 में दिल्ली में उनसे भेंट की।

संघ के कार्यक्रम में श्रीमती इंदिरा गांधी

वर्ष 1963 में स्वामी विवेकानंद जन्मशती के अवसर पर कन्याकुमारी में ह्लविवेकानंद शिला स्मारकह्व निर्माण के समय भी संघ ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख राजनेताओं एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया। स्मारक निर्माण के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 323 सांसदों के हस्ताक्षर एकनाथ रानाडे जी ने प्राप्त किये थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एकनाथ रानाडे जी के आमंत्रण पर ह्लविवेकानंद शिला स्मारक (विवेकानंद रॉक मेमोरियल) के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुईं।

कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन, दिव्यांग हुए सम्मानित

गीतों, गजलों और मुक्तक एवं हास्य में डूबे रहे श्रोता



देवरिया। शक्ति सदन फाउंडेशन एवं आरंभ एक आगाज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिव्यांग को यथासंभव धनराशि और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बतादें शक्ति सदन फाउंडेशन के तत्वावधान में पुस्तक विमोचन और काव्य फुहार संध्या आयोजित की गई। प्रोग्राम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि अरविंद अकेला ने की, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली बिहार से चल कर आए शानदार कवि पीतम कुमार झा उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में गजल ए गुलिस्तां की लेखिका अनामिका शर्मा ,सक्षम पाठक के साथ साथ डॉक्टर विनय मिश्रा,साधना त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।

शक्ति सदन फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर रीना मिश्रा द्वारा आयोजित किया किया गया तथा वरिष्ठ कवि प्रेम नाथ मिश्र ने संयोजन की भूमिका निभाई शानदार कवि प्रदीप मिश्र ने तथा प्रोग्राम की सफल रूप रेखा बनाने की जिम्मेदारी अजय कुमार पर रही और सभी लोगों ने जिम्मेदारी पूर्वक काम को अंजाम दिया।

प्रतिष्ठित कवि एवं मंच संचालक कवि हरे कृष्ण पांडेय ने शुरूआती संचालन इतना शानदार कर दिया कि आखिर तक उनकी आवाज की खनक लोग महसूस करते रहे तथा मुख्य संचालन उनकी निगरानी में वकार वाहिद ने अंजाम दिया। संतोष मिश्रा सोनी के सरस्वती वंदना से आरम्भ के कार्यक्रम का पवित्र आगाज हुआ, दयानन्द त्रिपाठी ने अपनी कविताओं से सबको चौंकाया, साधना सिंह को सुनना सबके लिए बेहद शानदार रहा कम समय में बड़ी कविता सुनाई। साधना एम जी इंटर कॉलेज के लेक्चरर विवेकानंद मिश्र ने हमेशा की तरह सादे हुए अंदाज में कविता सुनाई और कार्यक्रम को नया आयाम दिया।

कार्यक्रम में अजय कुमार का नया अंदाज देखने को मिला और उनकी शानदार गजलों एवं बेहतरीन आवाज व प्रस्तुति ने अचंभित कर दिया तथा उपस्थित लोग शब्दों के समन्दर में डूब गए।

गोरखपुर की प्रतिष्ठित कवयित्री डा सरिता सिंह ने जिंदगी और महिलाओं से जुड़े हुए जिन विषयों की बात की वो बेहद सराहनीय रहा तथा उनकी आवाज की खनक और अंदाज ने लोगों को तालियां बजाकर उनकी आवाज में आवाज मिलाने को मजबूर किया।अवधेश शर्मा नन्द जी ने छंद और दोहों के माध्यम से गहरी बात की और उनकी कविता के संदेश साथ लेकर लोग अपने घर को लौट , संतोष मिश्रा सोनी की कविताएं ,गजलें सीधे लोगों से जुड़ती रहीं और उन्होंने बहुत कम समय में बेहतर छाप छिड़ने का काम किया, इसी बीच शहर की समाज सेविका श्वेता मिश्रा ने अपने स्ट्रगल की कहानी बड़ी बेबाकी से सुनाई तथा लोगों को समाज का दूसरा पहलू दिखाकर सोचने पर मजबूर कर दिया। हरे कृष्ण पांडेय की कविताएं और तरन्नुम हमेशा की तरह लाजवाब रहा और तमाम लोगों से उनसे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया।

वरिष्ठ कवि प्रदीप मिश्र ने आरंभ एक आगाज के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए सबका आभार प्रकट किया तथा अपनी उत्कृष्ट रचनाओं की खुशबू को बिखेरते रहे और लोग मंत्रमुग्ध होते रहे, प्रेम नाथ मिश्र की कविताएं आहा क्या कहने , श्री मिश्र ने जब गीत पढ़ना शुरू किया तो वन्स मोर की आवाजें बुलंद होने लगीं तथा लोगों ने फरमाइश पर दूसरे गीत भी सुने।

समाजसेवी चंदन सिंह ने अपनी वाकपटुता से लोगों का ध्यान आकृष्ट किया तथा खूब तालियां बटोरा, शक्ति सदन फाउंडेशन की डायरेक्टर और कार्यक्रम आयोजिका डॉक्टर रीना मिश्रा ने बिल्कुल नया प्रयोग किया और हास्य के एक से बढ़के एक मुक्तक सुनाकर लोगों को हंसा हँसा के लोट पोट कर दिया तथा संस्था के तरफ से एक बच्चे का सम्मान और आर्थिक सहयोग भी किया कार्यक्रम का संचालन शायर वकार वाहिद कुशीनगर ने किया जो शानदार था।

सनातन की मजबूत नींव पर आकार ले रहा विकसित भारत : योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत बृहस्पतिवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपालदासजी महाराज के 87वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लिया। योगी ने इस दौरान अयोध्या के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मजबूत नींव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है तथा ह्यडबल इंजनह्ण की सरकार के प्रयासों से अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव की वापसी हो रही है। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन अत्यंत अभिभूत करने वाला और आनंदमयी है। उन्होंने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे पूज्य महंत नृत्यगोपालदासजी के जन्मदिवस समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनके दीघार्यु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

उन्होंने कहा कि पूज्य संतों की दिव्य साधना और आशीर्वाद के कारण ही भारत नए भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिना रुके और डिगे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन और प्राण प्रतिष्ठा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गत वर्ष 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और आज रामदरबार एवं राम मंदिर में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सनातन धर्म की मजबूत नींव का प्रतीक है। उन्होंने काशी, महाकाल, केदारपुरी और सोमनाथ मंदिरों के सौंदर्यीकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मंदिरों पर सनातन धर्म की मजबूत नींव टिकी है।

इस नींव पर मजबूत और भव्य भारत का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मणिरामदास छावनी के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी से 21वीं सदी तक, इस छावनी की 300 वर्षों की कठोर साधना का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि साक्षात माता जानकी ने इस परंपरा के संत को दर्शन दिए, जिसके कारण यह परंपरा फली-फूली। उन्होंने कहा कि महंत नृत्यगोपाल दास के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन को सफलता मिली और आज



अयोध्या विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित हो रही है। मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव की वापसी हो रही है तथा रामायण में वर्णित चौड़ी सड़कों और बाग-उपवनों वाली अयोध्या आज साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां चलती थीं, लेकिन आज श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत होता है। उन्होंने अयोध्या के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि आज सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राम की पैड़ी पर पहले काई जमी होती थी, लेकिन अब सरयू का जल स्वच्छ रहता है, पांच लाख श्रद्धालु एक साथ राम की पैड़ी में स्नान कर सकते हैं, नया घाट से गुप्तार घाट तक घाटों की नयी श्रृंखला स्थापित हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज ही के दिन महाराज भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप देवनदी गंगा धराधाम पर अवतरित हुई थीं।

उन्होंने कहा, मां गंगा हमारी मुक्ति और भुक्ति का कारक हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या में सरयू के जल को स्वच्छ रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के आधुनिक विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, माता शबरी के नाम पर भोजनालय, निषादराज के नाम पर यात्री विश्रामालय और महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं तुलसीदास के मंदिरों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में सभी दिव्य विभूतियों के विग्रह स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने गिद्धराज जटायू की भव्य मूर्ति की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि खानपान और पर्यावरणीय बदलाव के कारण गिद्धों की प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। उन्होंने कहा, गिद्ध मानवता के लिए उपकारी हैं। माता सीता के अपहरण के समय जटायू ने रावण से लोहा लिया था। इसीलिए राम जन्मभूमि पर उनकी भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। उन्होंने गोरखपुर में जटायू संरक्षण केंद्र की स्थापना का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी के सौंदर्यीकरण और हनुमत मंडपम के निर्माण की प्रशंसा की।

व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे का बेनकाब होना जरूरी

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा।



२बढ़ते तापमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की शानदार जीत के बाद आयोज्य जश्न के मातम, हाहाकार एवं दर्दनाक मंजर ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल ही नहीं खोली बल्कि सत्ता एवं खेल व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है। आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, यह राज्य प्रायोजित एवं प्रोत्साहित हत्या है। पुलिस का बंदोबस्त कहां था? चीख, पुकार और दर्द और क्रिकेट सितारों को देखने की दीवानगी एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक वाकया है जो सुदीर्घ काल तक पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़, निकासी मार्गों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक मामला है, जहाँ भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन एवं सत्ता का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है।

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा। लेकिन इस जीत के जश्न की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहें का होना और उसे खिलाडियों एवं राजनेताओं द्वारा नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें हो जाने के बावजूद जश्न जारी रहना, दुखद एवं शर्मनाक है। प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि खिलाड़ियों को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अवैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है। इस जीत के जश्न में हिस्सा लेने आई भीड़ का एक लाख तक होने का अनुमान था। लेकिन लंबे अंतराल के बाद मिली जीत ने लोगों के उत्साह को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि स्टेडियम के आसपास तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मौत की खबरें मिलने के बावजूद खिलाडियों के साथ जश्न मनाने में जुटा रहना उनकी प्रचार भूख का भौंडा उदाहरण है। जब मौत के बाद वहां पसरा मातम देखकर सब स्तब्ध थे तो सिद्धारमैया क्यों अपने पद की गरिमा एवं जिम्मेदारी को धूमिल कर रहे थे? सोचिए लोगों की मौत के बाद अगर एक मिनट भी जश्न मना, तालियां बजीं, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का मातम में बदलने का नेतृत्व करेगी तो आम लोगों का कांप उठना स्वाभाविक है।

बहरहाल, आईपीएल का आयोजन लगातार नई ऊंचाइयों को छूता हुआ व्यावसायिक क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने में जरूर सफल रहा है। फटाफट क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में भारत के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों विराट कोहली व एमएस धोनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अंततः विराट कोहली का आईपीएल खिताब जीतने का लंबा इंतजार इस जीत के साथ खत्म हुआ। लेकिन धोनी पांच बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग को जीत का खिताब दिलाने से चूक गए। एक तरह से आईपीएल क्रिकेट से कोहली की यह शानदार विदाई साबित हुई। वे इस गरिमामय विदाई के हकदार भी थे। उनके करोड़ों प्रशंसकों की कतारे देख कर राजनेता भी उनकी साथ मंच सांझा करने को उत्सुक दिखे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अन्य मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी भी इसी फिराक में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जश्न मनाते रहे और आमजनता अव्यवस्थाओं के कारण मौत में समाती रही। यह ऐसी दुखद घटना है जो अपनी निर्दयता एवं क्रूरता के लिये लम्बे समय तक कौंधती रहेगी। सिद्धारमैया के इस घटना की तुलना प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रही है।

भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रत्नागढ़ मंदिर में ढाँचागत कमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी। हालही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन एवं प्रयागराज में हुए हादसे में भी अनेकों लोगों की जान गयी। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियाँ में भी भीड़ प्रबंधन की पौल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों है? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बाधाओं को दूर करने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है।

रेलवे स्टेशन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त जगह और रास्ते नहीं हैं। कुछ स्थानों पर निकास मार्ग सीमित हैं या अनुपयुक्त हैं, जो भगदड़ का खतरा बढ़ाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों, जैसे कि एआई आधारित निगरानी और ड्रोन कैमरे का उपयोग सीमित है। लोगों को आपातकालीन निकास मार्गों, भीड़ नियंत्रण नियमों, और सुरक्षा उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। गलत सूचना या अचानक दहशत से भीड़ अनियंत्रित हो सकती है और भगदड़ मच सकती है। भीड़ का व्यवहार कई बार अनियंत्रित हो जाता है, खासकर धार्मिक, खेल एवं सिनेमा आयोजनों में, जहां लोग भावनाओं में बहकर आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। कई बार आयोजनकताओं और पुलिस के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे सुरक्षा चूक हो सकती है। भीड़ प्रबंधन केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों की संरचना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीतियों से गहनता से संबद्ध है। दुर्भाग्यवश, कई बार आयोजकों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते, जिससे जानमाल की हानि होती है। इस परिदृश्य में, बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की मौजूदा स्थिति, उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, हालिया घटनाओं से मिले सबक और प्रभावी समाधानों की चर्चा करना बेहद प्रासंगिक होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में धार्मिक उत्सव, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में लाखों लोग जुटते हैं। ऐसे आयोजनों के लिये पुलिस, होम गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाता है। विश्व के विभिन्न विकसित देशों में भीड़ प्रबंधन के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जापान जैसे देशों में रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ के प्रबंधन के लिये ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट सिस्टम स्थापित किये गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्टेडियमों, एयरपोर्ट्स एवं धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिये एआई आधारित कैमरे, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। हालाँकि भारत में बड़े आयोजनों के लिये प्रशासनिक तैयारियाँ की जाती हैं, फिर भी समय-समय पर कई कमियाँ उजागर होती रही हैं। लेकिन आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम के जश्न के दौरान खामियां ही खामियां देखने को मिली। ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन कोई आसान कार्य नहीं है। लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिये ठोस रणनीति, प्रशासनिक कौशल और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसका इस आयोजन में सर्वथा अभाव रहा। आखिर इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषी लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

डगमगाते पर्यावरण को संभालने का समय

वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी वैश्विक समस्या है। पिछले तीन दशकों से महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से ही जुड़ी है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण प्रकृति में लगातार बढ़ते दखल के कारण पृथ्वी पर बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। आधुनिक जीवनशैली, पृथ्वी पर पेड़-पौधों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण का विकराल रूप, मानव द्वारा प्रकृति का बेदर्दी से दोहन इत्यादि कारणों से मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन की भयावह खाई उत्पन्न हो रही है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित वातावरण के बढ़ते खतरे हम अब लगातार अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में ह्यविश्व पर्यावरण दिवसह्ण मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 16 जून 1972 को स्टॉकहोम में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था।

पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति के उचित दोहन को लेकर हालांकि यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीकी देशों में 1910 के दशक से ही समझौतों की शुरूआत हो गई थी किन्तु बीते कुछ दशकों में दुनिया के कई देशों ने इसे लेकर क्योटो प्रोटोकाल, मांट्रियल प्रोटोकाल, रियो सम्मलेन जैसे कई बहुराष्ट्रीय समझौते किए हैं। अधिकांश देशों की सरकारें पर्यावरण को लेकर चिंतित तो दिखती हैं लेकिन पर्यावरण की चिंता के बीच कुछ देश अपने हितों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की नीतियों में बदलाव करते रहे हैं। प्रदूषित वातावरण का खामियाजा केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि धरती पर विद्यमान प्रत्येक प्राणी को भुगतना पड़ता है। बड़े पैमाने पर प्रकृति से खिलवाड़ के ही कारण दुनिया के विशालकाय जंगल हर साल सुलगने लगे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को खरबों रुपये का नुकसान होने के अलावा दुर्लभ जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां भी भीषण आग में जलकर राख हो जाती हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दुनियाभर में पर्यावरण की स्थिति में सुधार देखा गया था, जिसने बता दिया था कि अगर हम चाहें तो पर्यावरण की स्थिति में काफी हद तक सुधार किया जा सकता है लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में निरन्तर हो रही बढ़ोतरी और मौसम का लगातार बिगड़ता मिजाज गहन चिंता का विषय बना है।

दलहन और तिलहन के उत्पादन पर योगी सरकार का फोकस

तेल और दाल ये दोनों हर किचन की रोजमर्रा की अनिवार्य उपयोग की चीजें हैं, इसीलिए कीमतों के लिहाज से ये बेहद संवेदनशील भी हैं। करीब 140 करोड़ की आबादी के नाते इनकी कीमतों में थोड़ी सी भी तेजी संवेदनशीलता को और बढ़ा देती है। चूंकि देश में इनका उत्पादन मांग की तुलना में कम है, लिहाजा भारत से थोड़ी भी अतिरिक्त मांग निकलने पर अंतराष्ट्रीय बाजार में भी इसका भाव चढ़ जाता है। यूं तो ये पूरे देश को प्रभावित करता है पर देश की सर्वाधिक आबादी की वजह से उत्तर प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित होता हो।

दलहन एवं तिलहन का रकबा और उपज बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास

ऐसा न हो। आम आदमी के थाल की दाल गाढ़ी रहे और तड़के के तेल की धार पतली न हो, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना सबसे जरूरी है। उत्पादन तभी बढ़ेगा जब किसान इनका रकबा बढ़ाएं और उत्पादित फसल का उचित दाम मिले। डबल इंजन की सरकार (मोदी एवं योगी सरकार) का इन दोनों पर फोकस है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा खरीफ की प्रमुख फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी इनके दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें एक दशक के दौरान दलहन और तिलहन की अलग अलग फसलों



की एमएसपी में 81 से लेकर 172 फीसद तक की वृद्धि हुई है। सबसे कम 81 फीसद की वृद्धि मूंगफली और सबसे अधिक 172 फीसद की वृद्धि नाइजर सीड में हुई है।

एमएसपी के जरिए उत्पादन करने वाले किसानों को लागत के अनुसार उचित दाम दिलाने के साथ सरकार इनका रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की जागरूक करने के साथ हरसंभव सहयोग भी कर रही है। देश में अब तक के सबसे बड़े अभियान विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों को दलहन एवं तिलहन की उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, इस अभियान के दौरान योगी सरकार प्रगतिशील किसानों में 4,58,000 निःशुल्क मिनीकिट भी बांटेगी, जिसमें दलहन, उर्द, मूंग, अरहर के 1,05,000, तिल के 1,00,000, मूंगफली के 6,000 किट होंगे।

सरकार दलहन और तिलहन मिशन भी चला रही है। दलहन को योगी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना एक जिला, एक उत्पाद (ओडी ओपी) में भी शामिल कर रखा है। दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार दलहन ग्राम योजना भी चला रही है। इस सबके नतीजे भी दिख रहे हैं।

आठ साल में 128 प्रतिशत बढ़ा तिलहनी फसलों का उत्पादन

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2016/2017 में तिलहन का उत्पादन मात्र 12.40 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 20.31 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह 128% की अभूतपूर्व वृद्धि है। इसी तरह की वृद्धि दलहन की फसलों में भी हुई। बुंदेलखंड और पूर्वांचल को केंद्र में रखकर विश्वबैंक की मदद से चल रही यूपी एग्रीज जैसी महत्वाकांक्षी योजना के जरिए दलहन एवं तिलहन का रकबा और उपज बढ़ने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादक: पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com